राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

कार्यान्वयन का स्वरूप

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

भीतरी मुखपृष्ठ : गांधी/तिलस्म

विषयवस्तु

प्रस्तावना		i-ii
पुनरावलोकन		iii-x
1.	सामाजिक समावेशन, जुटाव तथा संस्थापन	1–4
2.	वित्तीय समावेशन	5–12
3.	आजीविका	13–21
4.	तालमेल तथा सहभागिता	22–24
5.	पंचायत राज संस्थाएं	25–26
6.	सहायक अवसंरचनाएं	27–32
7.	निगरानी, मूल्यांकन तथा शिक्षण	33–34
8.	वित्तीय प्रबंधन	35–38
9.	कार्यान्वयन	39–46
अनुबंध		47
अनुबंध-1:	केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति – संघटन	47
अनुबंध-2:	एनआरएलएम सलाहकार, समन्वय तथा अधिकार – प्राप्त समितियां नवीन आजीविका परियोजनाओं तथा बहुराज्यीय कौशल एवं नियोजन परियोजनाओं हेतु परियोजना जांच एवं अनुमोदन समितियां	48
अनुबंध-3:	एसआरएलएम राज्य सोसायटी : शासी निकाय तथा कार्यकारी समिति का निदर्शनात्मक संघटन	50
अनुबंध-4:	टेम्पलेट्स : पारिस्थितिक विश्लेषण, संदर्शी योजना, वार्षिक योजना उपयोग किये गए शब्दकोश, लघु नाम तथा संक्षिप्त रूप	51

रिक्त

भीतरी पश्च कवर : एसएपीएपी/निर्धनता एक अभिशाप है

प्रस्तावना

गरीब परिवारों के लिए परिसम्पत्तियों के सृजन तथा स्वरोजगार हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों की वर्ष 1980 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) से शुरूआत की गई थी । इस संबंध में 1999 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जब आईआरडीपी को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के रूप में परिवर्तित किया गया । गरीबों को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में संगठित करके स्व-रोजगार उपलब्ध कराना, नई रणनीति का मुख्य अंग था । राज्यों में, गरीबी के उन्मूलन हेतु गरीबों को एसएचजी में संगठित करने को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जा रहा है । 2.5 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को संगठित करके एसएचजी नेटवर्क में समाहित किया गया है ।

एसजीएसवाई की व्यवस्थित समीक्षा से निम्नलिखित जैसी कुछ कमियां सामने आई हैं - ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण, सामुदायिक संस्थापन के लिए अपर्याप्त निवेश और बैंकों के साथ कम लिंकेज, जिसके परिणामस्वरूप कम ऋण की उपलब्धता तथा दोहरा वित्तपोषण । अनेक राज्य एसजीएसवाई के तहत प्राप्त निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं । एसएचजी परिसंघों की तरह निर्धनों के समग्र संस्थापन की अनुपस्थिति के कारण निर्धन उत्पादकता वृद्धि, विपणन लिंकेज, जोखिम प्रबंधन आदि के लिए अधिक सहायता प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं । अनेक मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि एसजीएसवाई योजना से वहां ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में सफलता मिली है, जहां गरीबों के एसएचजी के रूप में व्यवस्थित जुटाव एवं उनके क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास को प्रक्रियोन्मुख रूप से कार्यान्वित किया गया है । अन्य क्षेत्रों में इतना प्रभाव नही हुआ है ।

अपूर्ण कार्य की मात्रा बहुत अधिक है । अनुमानित 7.0 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों (बीपीएल परिवारों के 2010 अनुमान) में से 4.5 करोड़ परिवारों को अभी भी एसएचजी में संगठित किया जाना है । विद्यमान एसएचजी को भी और अधिक सुदृढ़ किया जाना तथा उन्हें अधिक वित्तीय सहायता दी जानी आवश्यक है । इस पृष्ठभूमि में सरकार ने एसजीएसवाई के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन को अनुमोदित किया है जिसे सम्पूर्ण देश में मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित किया जाना है ।

एनआरएलएम के अधिदेश में सभी निर्धन परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करना, उन्हें स्थायी जीविका अवसर उपलब्ध कराना और गरीबी से ऊपर आने तक उनका पोषण करना निहित है, ताकि वे अच्छा जीवन बसर कर सकें । इसके लिए एनआरएलएम में विभिन्न स्तरों पर समर्पित एवं संवेदनशील सहायता संरचनाओं की व्यवस्था की गई है । इनसे निर्धनों की क्षमता में बढ़ोतरी होती है और वे बाहरी माहौल से तारतम्य बैठाने, वित्त एवं अन्य संसाधन प्राप्त करने और विभिन्न स्तरों पर संस्थापन के लिए सक्षम बनते हैं । उक्त संस्थापन से उन्हें शुरू में संगठित करने, आजीविका सेवाएं उपलब्ध कराने और बाद में आजीविका को स्थायी बनाने में सहायता मिलती है । उक्त सहायक संरचनाओं का बेरोजगार ग्रामीण निर्धन युवाओं के कौशल विकास तथा विशेष रूप से विकसित क्षेत्रों में नौकरियों में रोजगार उपलब्ध कराने अथवा लाभकारी स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ।

निर्धनों के एसएचजी के रूप में संस्थापन, उनके परिसंघों तथा आजीविका के विविध रूपों से निर्धनों को स्व-सहायता तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित सामूहिक कार्रवाई के लिए मंच उपलब्ध होता है । वे निर्धनों की ओर से मांग का आधार बनते हैं। इससे उनकी आजीविका संबंधी मुद्दों तथा निर्धनता के अन्य पहलुओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए बैंकों तथा सरकारी विभागों सहित प्रमुख संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है । ये संस्थान उपभोग संबंधी जरूरतों, ऋणमोचन, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आजीविका सहित उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचत, ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं । वे सदस्यों की जानकारी, उनके कौशल, परिसम्पत्तियों, अवसंरचनाओं, स्वयं की निधियों तथा अन्य संसाधनों में वृद्धि करते हैं । वे सदस्यों की आय में बढ़ोतरी करते हैं, व्यय में कमी करते हैं, लाभदायक रोजगार में वृद्धि करते हैं और जोखिम में कमी करते हैं । वे उन्हें जागरूक भी बनाते हैं तथा उनकी मोल-तोल क्षमता में वृद्धि करते हैं और सदस्यों के अनुकूल नीतियां बनाते हैं ।

निर्धनों को संस्थागत रूप से एकजुट करने के लिए बाहरी अनुकूल सहायता उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है । सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन तथा सिविल सोसायटी संगठन, स्थानीय सरकारें, बैंक तथा नैगम क्षेत्र यह भूमिका निभा सकते हैं । समय के साथ-साथ ये संस्थान परिपक्व होने पर निर्धनों के लिए आंतरिक सहायता संरचनाओं तथा संस्थानों का काम करते हैं । उनके सफल सदस्य तथा अधिकार-सम्पन्न नेता इन प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं । इस प्रकार निर्धनों के लिए कार्यक्रम, निर्धनों द्वारा एवं निर्धनों के कार्यक्रमों का रूप लेते हैं । निर्धनता एक जटिल तथा बहुआयामी समस्या है, इसलिए निर्धनों के संस्थानों का विविध क्षेत्रों में एवं सेवा प्रदाताओं के रूप में उपयोग किया जाता है । समय के साथ-साथ उनकी दक्षता एवं कारगरपन में भी सुधार होता है । तथापि, प्रारंभिक स्थिति के बाद प्रगति में तेजी आती है और गुणवत्ता में सुधार होता है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों, बैंकरों एवं विद्वानों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर एनआरएलएम स्वरूप को तैयार किया गया है । एनआरएलएम एक शुरूआती मिशन है और इसे गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रक्रियाओं तथा असफलताओं के अनुभव से और बेहतर बनाया जाएगा । एनआरएलएम की तरह, इसका कार्यान्वयन स्वरूप प्रारंभिक, क्रियाशील तथा गतिशील स्वरूप है । इस एनआरएलएम स्वरूप से स्थानीय स्थितियों पर आधारित स्थानीय योजनाओं में सहायता मिलती है और कार्यान्वयन में प्रगति के साथ-साथ प्राप्त अनुभव से जानकारी में वृद्धि होती है ।

उक्त स्वरूप के दो भाग हैं - 'हार्ड' पार्ट तथा 'सॉफ्ट' पार्ट । 'हार्ड' पार्ट में वित्तपोषण मानक तथा विभिन्न घटकों के वित्तपोषण संबंधी सीमा और राज्यों में पारस्परिक आबंटन शामिल है । सॉफ्ट पार्ट में अन्य सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं । ये केवल निदर्शनात्मक हैं न कि अनिवार्य । ये इस समय देश में प्रचलित अधिकांश प्रक्रियाओं से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं । प्रत्येक राज्य द्वारा अपने स्वयं के प्रचालन दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए । कार्यान्वयन में प्रगति के साथ-साथ विषयपरक एवं मुद्दा -आधारित राष्ट्रीय प्रचालनात्मक नियमावली भी उपलब्ध होगी ।

एनआरएलएम में विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता संरचनाओं तथा संगठनों के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने और उनकी क्षमता में वृद्धि, वित्तीय स्थिति एवं स्व-प्रबंधित आत्मनिर्भर संगठनों, रोजगार, लाभकारी स्व-रोजगार एवं उद्यमों के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया है । निर्धनों के संगठन बाद में अपने सदस्यों की आजीविका सुनिश्चित करने, उनके जीवन स्तर एवं लाभ में सुधार करने का प्रयास करते हैं ।

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में मुख्य रूप से यह धारणा निहित है कि निर्धनों में गरीबी से उबरने की अत्यधिक इच्छा है और क्षमता भी है । वे उद्यमी हैं । इस संबंध में मुख्य चुनौती, सार्थक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए उनकी क्षमता का उपयोग करने की है, जिससे उन्हें गरीबी से बाहर लाया जा सके । इस प्रक्रिया में पहला कदम उन्हें अपने स्वयं के संगठन बनाने हेतु प्रोत्साहित करना है । उनकी सही क्षमता का आकलन तभी हो सकता है, जब उन्हें बाहरी परिस्थितियों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सामर्थ्य उपलब्ध कराया जाए एवं सुगम वित्त की व्यवस्था की जाए तथा उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने एवं सार्थक जीविका के रूप में परिवर्तित करने के योग्य बनाया जाए । इसके लिए उनके संगठनों की सतत सहायता आवश्यक है । उक्त सामाजिक एकजुटता, संस्थापन तथा जीविका प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्तर से उप जिला स्तर तक एक बाहरी समर्पित, संवदेनशील सहायता संरचना आवश्यक है ।

गरीबों के मजबूत सांस्थानिक मंचों से गरीब परिवारों को अधिकार - सम्पन्न बनाने और उनके स्वयं के मानवीय, सामाजिक, वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की प्राप्ति में सहायता मिलती है । इनसे उन्हें सेवाओं (सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों से) सहित अपने अधिकारों, हकदारी तथा आजीविका अवसरों की जानकारी मिलती है । सामाजिक एकजुटता प्रक्रिया से गरीबों की एकात्मता, अपनी बात कहने तथा मोलतोल करने की क्षमता में वृद्धि होती है । इन प्रक्रियाओं से उन्हें स्वयं के संसाधनों, कौशल तथा प्राथमिकताओं के माध्यम से व्यवहार्य आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिलती है । इसके फलस्वरूप, वे गरीबी से सतत रूप से बाहर निकलने में सफल हो सकते हैं ।

एनआरएलएम में यह भी निहित है कि यदि इस कार्यक्रम को गरीबों द्वारा स्वयं संचालित किया जाए तो इसका समयबद्ध रूप से विस्तार किया जा सकता है ।

मिशन, सिद्धांत, मूल्य

एनआरएलएम मिशन

''गरीब परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित मजदूरी रोजगार अवसर उपलब्ध कराकर निर्धनता कम करना, ताकि गरीबों के मजबूत बुनियादी संस्थापन के माध्यम से उनकी जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके ।''

एनआरएलएम दिशा-निर्देशक सिद्धांत

- गरीबों में गरीबी से निज़ात पाने की तीव्र इच्छा होती है और इस संबंध में उनमें क्षमता भी होती है ।
- गरीबों की क्षमता के उपयोग के लिए सामाजिक एकजुटता तथा मजबूत संस्थागत महत्वपूर्ण हैं ।
- सामाजिक एकजुटता, संस्थापन तथा अधिकारिता के लिए एक बाहरी समर्पित एवं संवेदनशील सहायता संरचना आवश्यक है ।

- इस बेहतरी के लिए जानकारी का प्रचार-प्रसार, कौशल विकास, ऋण एवं बाजार तथा अन्य आजीविका सेवाओं की अत्यावश्यकता होती है ।

एनआरएलएम मूल्य

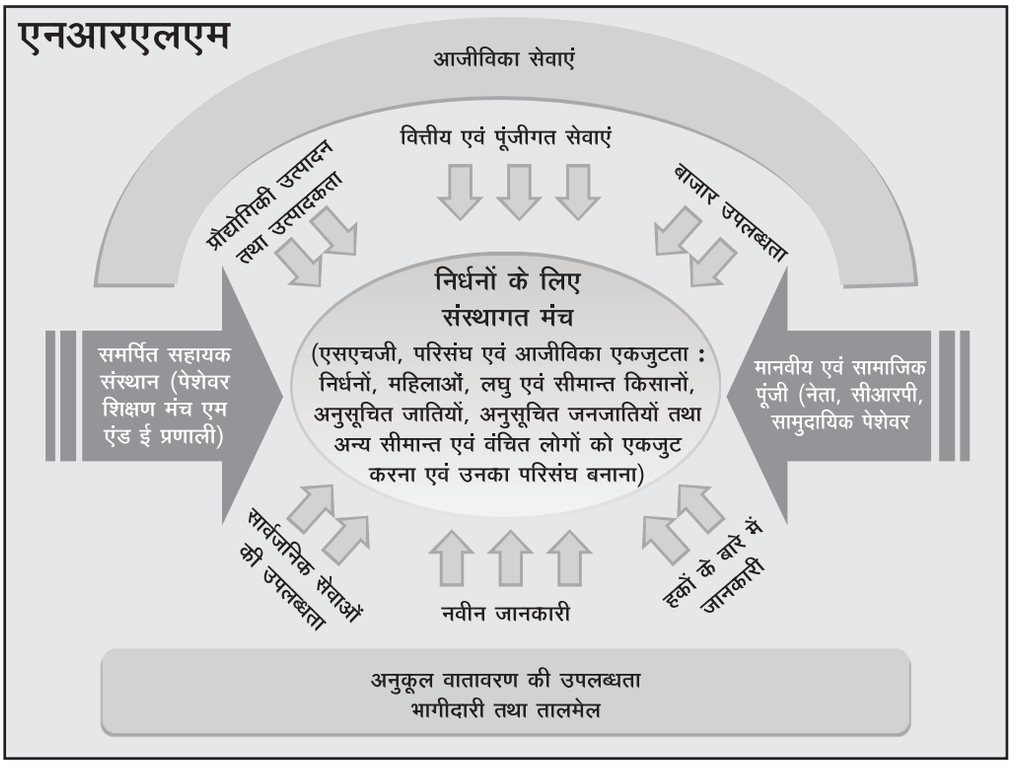
एनआरएलएम के अंतर्गत सभी कार्यकलापों के संबंध में मुख्य दिशा-निर्देशक मूल्य निम्नानुसार हैं :-

- सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना
- सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थापन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना
- आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी सभी स्तरों पर गरीबों का स्वामित्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना
- सामुदायिक स्व-निर्भरता ।

दृष्टिकोण

गरीबों को स्थायी रूप से आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनआरएलएम में उनकी क्षमता के संवर्धन (जानकारी, कौशल विकास, वित्तपोषण एवं एकजुटता के माध्यम से) की व्यवस्था की गई है, ताकि तेजी से हो रहे बाहरी बदलाव के अनुसार वे स्वयं को ढाल सकें । विविध आजीविका कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए एनआरएलएम तीन आधारों पर कार्य करता है - गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, बाहरी क्षेत्र में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना और स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता (माइक्रो उद्यमों के लिए) को प्रोत्साहित करना ।

समर्पित सहायक संरचनाओं से निर्धनों के संस्थापन को मजबूत करने में सहायता मिलती है। मानवीय एवं सामाजिक पूंजी सहित इस संस्थापन से इसके निर्धन सदस्यों को विविध आजीविका सेवाएं उपलब्ध होती हैं । इन सेवाओं में वित्तीय एवं पूंजीगत सेवाएं, उत्पादन एवं उत्पादकता संवर्धन सेवाएं, प्रौद्योगिकी, जानकारी, कौशल, बाजार सम्बद्धता आदि शामिल हैं । इसके माध्यम से विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच तालमेल एवं भागीदारी सुनिश्चित होती है और निर्धनों को अपने अधिकारों एवं हकों, सार्वजनिक सेवाओं तथा नवीन बातों के बारे में अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है । निर्धनों के संस्थापक के माध्यम से उनकी एकजुटता से प्रत्येक सदस्य के संबंध में ट्रांजेक्शन लागत में कमी आती है, उनकी आजीविका अधिक सुगम बनती है और निर्धनता दूर करने के अधिक अवसर मिलते हैं ।



इच्छुक ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए परामर्श के बाद तथा संबंधित जॉब अपेक्षाओं के अनुकूल योग्यता के अनुसार कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी तथा लाभकारी जॉब उपलब्ध कराए जाएंगे । स्व-रोजगार में लगे तथा उद्यमी निर्धनों का कौशल विकास किया जाएगा तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन उत्पादों एवं सेवाओं जिनकी मांग है, के लघु उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी ।

एनआरएलएम का कार्यान्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है । इससे निम्नलिखित में सहायता मिलेगी - (क) वर्तमान आबंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति अपनाना, ताकि राज्य स्वयं की आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन योजनाएं बना सकें, (ख) लक्ष्यों, परिणामों तथा समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करना (ग) सतत क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं गरीबों तथा संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना और (घ) गरीबी उन्मूलन संबंधी परिणामों के लक्ष्यों की निगरानी करना । चूंकि एनआरएलएम मांग आधारित रणनीति पर आधारित है, इसलिए राज्य गरीबी उन्मूलन के लिए अपनी स्वयं की आजीविका आधारित संदर्शी योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं बना सकते हैं । समग्र योजनाएं, राज्य के लिए आबंटन के अंतर्गत होंगी, जो कि पारस्परिक गरीबी अनुपात पर आधारित होंगी। समय के साथ-साथ, गरीबों के संस्थापन की परिपक्वता के फलस्वरूप वे निचले स्तर पर आयोजना कर पाएंगे ।

एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं

सामाजिक समावेशन तथा निर्धनों का संस्थापन

1. सार्वभौम सामाजिक एकजुटता : शुरू में, एनआरएलएम के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्दिष्ट ग्रामीण निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूह

(एसएचजी) में शामिल किया जाएगा । बाद में, महिलाओं तथा पुरूषों दोनों को किसान संघों, दुग्ध उत्पादक सहकारिताओं, बुनकर परिसंघों आदि के रूप में संगठित किया जाएगा, ताकि आजीविका संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके । ये सभी संगठन समावेशी प्रकृति के हैं और इसमें प्रत्येक गरीब व्यक्ति को शामिल किया जाएगा । एनआरएलएम के तहत समाज के वंचित वर्गों की पर्याप्त कवरेज इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि बीपीएल परिवारों की 100% कवरेज के लक्ष्यों पर विचार करते समय 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के हों, 15% अल्पसंख्यक हों तथा 3% विकलांग हों ।

2. गरीबों के संस्थापन को प्रोत्साहित करना : गरीबों के विचारों पर ध्यान देने और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने तथा बाहरी एजेंसियों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए एसएचजी तथा उनके ग्राम स्तरीय एवं उच्च स्तरीय परिसंघों में उनका सुदृढ़ संस्थापन आवश्यक है । वे उन्हें अधिकार-सम्पन्न बनाते हैं तथा जानकारी एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के साधन और उत्पादन, एकजुटता तथा वाणिज्य के केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं । इसलिए एनआरएलएम में इन संगठनों की विभिन्न स्तरों पर स्थापना पर ध्यान दिया जाएगा ।

इसके अलावा, एआरएलएम आजीविका समूहन, उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं/उन्नयन के माध्यम से आजीविका प्रोत्साहन संबंधी कम्पनियों, बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज जैसे विशिष्ट संस्थापनों और जानकारी, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि तक पहुंच को प्रोत्साहित करेगा । आजीविका समूहन से निर्धनों को अपने सीमित संसाधनों को इष्टतम करने में सहायता मिलेगी ।

सरकारी प्रयासों तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों से निर्धन महिलाओं के संस्थान स्थापित किए गए हैं । एनआरएलएम से निर्धनों के विद्यमान संस्थानों को भागीदारी मोड में सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी । सरकारी तथा एनजीओ दोनों क्षेत्रों में स्व-सहायता प्रोत्साहक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा । इसके अलावा, विद्यमान संस्थान तथा उनके नेताओं एवं स्टॉफ द्वारा नए संस्थानों को स्थापित करने और उनके पोषण को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

3. प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास : एनआरएलएम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धनों का निम्नलिखित के लिए कौशल विकास हो - संस्थानों का प्रबंधन, बाजार से सम्बद्धता, उनकी आजीविका का प्रबंधन, ऋण उपभोग क्षमता बढ़ाना एवं ऋण उपयुक्तता आदि । लक्षित परिवारों, एसएचजी, उनके परिसंघों, सरकारी कर्मियों, बैंकरों, एनजीओ तथा अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डरों के सतत क्षमता निर्माण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की कल्पना की गई है। विशेष रूप से एसएचजी एवं उनके परिसंघों तथा अन्य समूहों के क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक पेशेवरों तथा सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने पर बल दिया जाएगा । एनआरएलएम के तहत, जानकारी का प्रचार-प्रसार तथा क्षमता निर्माण प्रभावी रूप से करने के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

4. परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी : परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी के रूप में सब्सिडी उपलब्ध करायी जाएगी । एसएचजी को परिक्रामी निधि (70% से अधिक सदस्य बीपीएल परिवारों से संबंधित होने पर), प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी ताकि उनमें मितव्ययिता और दीर्घकालिक रूप से ऋण संबंधी आवश्यकताओं और अल्पकालिक रूप से तात्कालिक उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निधियां एकत्र करने की आदत उत्पन्न हो सके । उक्त सब्सिडी कार्पस के रूप में होगी और इसे सदस्यों की ऋण आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप से पूरी करने तथा

दोबारा बैंक वित्तपोषण की पूर्ति हेतु उत्प्रेरक पूंजी के रूप में उपयोग किया जाएगा । पूंजीगत सब्सिडी निधि एसएचजी को सीधे दी जाएगी अथवा परिसंघों के माध्यम से एसएचजी को दी जाएगी, यदि वे चाहेंगे । निर्धनता से उबरने के लिए तर्कसंगत दरों पर सतत आधार पर सुगमता से वित्त की उपलब्धता प्रमुख कारक है, जब तक वे अपनी स्वयं की निधियां अधिक मात्रा में एकत्र न कर लें ।

5. सार्वभौम वित्तीय समावेशन : एनआरएलएम के माध्यम से सभी गरीब परिवारों, स्व-सहायता समूहों तथा उनके परिसंघों को आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सार्वभौम वित्तीय समावेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें वित्तीय समावेशन के मांग एवं आपूर्ति दोनों पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा । मांग के संदर्भ में इसके द्वारा गरीबों को वित्तीय पहलू के बारे में जानकारी दी जाएगी और एसएचजी और उनके परिसंघों के लिए उत्प्रेरक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी । आपूति के संदर्भ में इसके अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करते हुए सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, बिजनेस कोरेसपोन्डेन्ट और 'बैंक मित्र' जैसे सामुदायिक सुविधादाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा । जीवन संबंधी हानि, स्वास्थ्य तथा परिसम्पत्तियों के संदर्भ में ग्रामीण गरीबों के एकसमान कवरेज पर भी ध्यान दिया जाएगा । इसके अलावा, इसके तहत विशेष रूप से स्थानीय प्रवसन वाले क्षेत्रों में धन प्रेषण की व्यवस्था की जाएगी ।

6. ब्याज सब्सिडी का प्रावधान : ग्रामीण निर्धनों को अपने उद्यमों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कम दर पर और विभिन्न अंतरालों पर ऋण की आवश्यकता होती है । ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए एनआरएलएम के तहत उन सभी पात्र एसएचजी को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिन्होंने प्रमुख वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है, जो कि सही समय पर ऋण की वापसी पर आधारित है (यह किसी एसएचजी द्वारा पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने की स्थिति में लागू नहीं होगा । उक्त एसएचजी को ब्याज आधारित सब्सिडी तभी दी जाएगी, जब उसके द्वारा पूंजीगत सब्सिडी आधारित ऋण वापस करने के बाद नया ऋण लिया जाएगा)। यह सब्सिडी एसएचजी को उस स्थिति में उपलब्ध होगी जब उसके कम से कम 70% सदस्य बीपीएल परिवारों से हों और इसकी सीमा संचयी ऋण के माध्यम से 1.00 लाख रू0 प्रति परिवार होगी ।

7. आजीविका : गरीब उत्तरजीविता के लिए बहुविध आजीविका साधन अपनाते हैं । वर्तमान में उनके प्रमुख आजीविका साधन इस प्रकार हैं - मजदूरी, लघु एवं सीमान्त कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्यपालन और पारंपरिक गैर-कृषि व्यवसाय । वर्तमान आजीविका से आय तथा रोजगार, उनके व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । एनआरएलएम से प्रत्येक गरीब परिवार की आजीविका के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए स्थायी आजीविका तथा उसमें वृद्धि और विविधता सुनिश्चित की जाएगी ।

8. अवसंरचनाओं का सृजन तथा बाजार सहायता : एनआरएलएम से गरीबों की प्रमुख आजीविका आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा । इससे निर्धनों की बाजार संबंधी जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा । बाजार संबंधी सहायता में ये शामिल हैं - बाजार अनुसंधान, बाजार संबंधी जानकारी, प्रौद्योगिकी का विस्तार, बैकवार्ड एवं फारवार्ड लिंकेज विकसित करना, आजीविका का समूहकरण करना और उनकी व्यापार संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहित करना । एनआरएलएम के अंतर्गत इन कार्यकलापों विशेष रूप से बाजार लिंकेज के लिए सार्वजनिक तथा निजी संगठनों तथा उनके नेटवर्कों/एसोसिएशनों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा । ग्रामीण बाजारों को उत्पादक समूहों

(एसएचजी) तथा वैयक्तिक उत्पादकों को शहरी तथा अर्द्ध-बाहरी बाजारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध किया जाएगा, जिसके लिए लाभार्थियों के सतत रूप से निर्धारण एवं क्रमावर्तन संबंधी पूर्ण रूप से विकसित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा । राज्य के कार्यक्रम परिव्यय का 20% (पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में 25%) इस प्रयोजन के लिए रखा गया है ।

9. कौशल विकास तथा नियोजन परियोजनाएं : एनआरएलएम के माध्यम से युवाओं के मामले में बेहतर निवेश के रूप में भागीदारी मोड के माध्यम से विद्यमान कौशल एवं नियोजन परियोजनाओं का उन्नयन किया जाएगा और उभरते बाजारों में आजीविका अवसरों को प्रोत्साहन मिलेगा । इसे सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक, निजी, गैर-सरकारी तथा सामुदायिक संगठनों के साथ भागीदारी के विभिन्न मॉडल विकसित किए जाएंगे । औद्योगिक एसोसिशनों तथा क्षेत्र विशिष्ट कर्मचारी एसोसिएशनों के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाएंगे । इस प्रयास में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) अग्रणी भागीदार होगा । इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय आबंटन का 15% नियत किया गया है ।

10. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

एनआरएलएम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है । आरएसईटीआई जिले बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार वाले उद्यमियों के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसे आवश्यकता आधारित प्रयोगात्मक शिक्षण कार्यक्रम और मौके पर व्यवस्थित सहायता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । बैंक चयन, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण पश्चात चरणों संबंधी कार्यों में पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं । आरएसइटीआई गरीबों के संगठनों सहित अन्य संगठनों की सहायता से अपनी कार्यसूची तथा उन्हें दिए गए अधिदेश को पूरा करते हैं ।

11. नवीनीकरण : एनआरएलएम में यह अवधारणा निहित है कि सफल नवीनीकरण से गरीबी को काफी तेजी से कम किया जा सकता है । इसीलिए केन्द्रीय आबंटन का 5% नवीनीकरण के लिए नियत किया जाता है । उन नवीन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे निर्धनता एवं अधिकतम गरीब परिवारों को लाभ पहुंचे और सीमित संसाधनों से अधिकतम प्रभाव हो ।

तालमेल तथा भागीदारी

12. तालमेल : एनआरएलएम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ तालमेल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि प्रत्यक्ष रूप से तथा गरीबों के संगठनों के माध्यम से सहक्रिया सुनिश्चित की जा सके ।

13. गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साझेदारीः

एनआरएलएम दो स्तरों- कार्यनीतिगत और कार्यान्वयन-पर सक्रिय रूप से गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य सिविल सोसाइटी (सीएसओ) के साथ साझेदारी करने का प्रयत्न करेगा । इस साझेदारी का मार्गदर्शन एनआरएलएम की मुख्य धारणाओं तथा नैतिक मूल्यों एवं प्रक्रिया और परिणाम संबंधी पारस्परिक करार के जरिए किया

जाएगा । एनआरएलएम गैर सरकारी संगठनों और अन्य सीएसओ के साथ साझेदारी के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाएगा । इसके अलावा, एनआरएलएम में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ सीधे या निर्धनों की संस्थाओं के जरिए साझेदारी करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

14. पीआरई के साथ संपर्कः पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की मुख्य भूमिका, जिसमें शासी, वाणिज्यिक और राजनैतिक भूमिकाएं शामिल हैं, को देखते हुए खासकर ग्राम पंचायतों के स्तर पर पंचायतों और निर्धनों की संस्थाओं के बीच सावधानीपूर्वक पारस्परिक रूप से लाभप्रद कामकाजी संबंध बनाने एवं इसे आसान बनाने की जरूरत है । पारस्परिक राय, सहायता और संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए ऐसी संस्थाओं और पीआरआई के बीच नियमित रूप से परामर्श करने के लिए औपचारिक प्लेटफार्म बनाए जाएंगे । तथापि, उनकी स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरती जाएगी । जहां कोई पीआरआई नहीं हैं, वहां पारंपरिक स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं से संपर्क किया जाएगा ।

15. संवेदनशील सहायक संरचनाएं: एनआरएलएम की प्रक्रियात्मक गहन प्रयासों में समर्पित मानव संसाधनों की जरूरत होगी । इसे स्वीकारते हुए, एनआरएलएम राष्ट्र, राज्य, जिला एवं उप-जिला स्तरों पर संवेदनशील और समर्पित सहायक संरचना बनाएगा । इन सहायक संरचनाओं में राष्ट्र स्तर पर एनआरएलएम परामर्शदात्री, समन्वयन एवं अधिकार प्राप्त समितियां तथा राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाइयां राज्य स्तर पर स्वायत्तशासी निकायों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राज्य मिशन प्रबंधन इकाइयां, जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन इकाइयां और ब्लॉक और/या क्लस्टर स्तरों पर उप-जिला इकाइयां शामिल होंगी । निर्धनों की संस्थाएं, उनके स्टाफ और अन्य सामाजिक पूंजी भी सहायता उपलब्ध कराएगी । ये संस्थाएं सरकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और पीआरआई से उचित रूप से जुड़ी रहेंगी । निर्धनों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ डीआरडीए के शासन को बेहतर एवं पेशेवर बनाया जाएगा ताकि वे गरीबों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें । इन सहायक संरचनाओं में साझेदारी और सेवाओं की आउटसोर्सिंग सहित उपयुक्त व्यवस्थाओं के जरिए पेशेवर रूप से सक्षम और समर्पित मानव संसाधनों की भर्ती की जाएगी ।

16. तकनीकी सहायताः एनआरएलएम अपने प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से राज्य और अन्य सभी साझेदारों की संस्थागत क्षमताएं सृजित करने और सुदृढ़ करने के लिए उन्हें तकनीकी सहायता मुहैया कराएगा । यह राष्ट्रीय ज्ञान प्रबंधन और शिक्षण फोरम/व्यवस्था बनाएगा । यह दूर-दराज के क्षेत्रों में रहन वाले निर्धनों की संस्थाओं तथा बैंकिंग क्षेत्रों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी बढ़ाने में मदद करेगा । यह सामाजिक एकजुटता, संस्थागत निर्माण, माइक्रो फाइनेंस, आजीविका, कौशल विकास उद्यमिता आदि सहित सभी संबंध विधाओं में विशेषज्ञों, काम करने वालों और सलाहकार का एक राष्ट्रीय पुल बनाएगा । वे राज्य गरीबी उपशमन कार्यनीतियां बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एसआरएलएम को मौके पर सहायता भी उपलब्ध कराएगा ।

17. निगरानी एवं शिक्षणः एनआरएलएम बेब आधारित व्यापक एमआईएस, निष्पादन समीक्षा समिति की नियमित बैठकों, वरिष्ठ सहकर्मियों, स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय निगरानी समूहों के दौरों तथा समीक्षा एवं नियोजन मिशनों के तंत्रों के जरिए अपने परिणामों, प्रक्रियाओं और क्रियाकलापों की निगरानी करेगा । प्रक्रिया निगरानी के अध्ययनों, विषयगत अध्ययनों और प्रभाव मूल्यांकनों से भी उपर्युक्त के लिए जानकारी मिलेगी । बेहतर पारदर्शिता लाने की दृष्टि से यह सामाजिक रूप से जवाबदेह कार्यों को भी बढ़ावा देगा । यह एसआरएलएम और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं से अलग होगा । एक दूसरे से मिली जानकारी एनआरएलएम में शिक्षण की प्रमुख प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करती है ।

18. वित्तपोषण पद्धतिः एनआरएलएम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90: 10; संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्र से शत प्रतिशत) । राज्यों के लिए निर्धारित केन्द्रीय आबंटन का वितरण राज्यों में गरीबी की व्यापकता के आधार पर किया जाएगा ।

19. चरणबद्ध कार्यान्वयनः निर्धनों की सामाजिक पूंजी निर्धनों की संस्थाओं, उनके प्रमुखों, सामुदायिक पेशेवरों और मुख्य रूप से सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (निर्धन महिलाएं जिनका जीवन उनकी संस्थाओं की सहायता के जरिए बदल गया है) से बनती है । प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक पूंजी बनने में कुछ समय लगता है, किन्तु कुछ समय पश्चात इसमें कई गुणा वृद्धि हो जाती है । यदि निर्धनों की सामाजिक पूंजी एनआरएलएम में प्रमुख भूमिका नहीं निभाएगी तो यह लोगों का कार्यक्रम नहीं बनेगा । इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नई पहलों की गुणवत्ता और प्रभाविकता कम न हो । इसलिए, एनआरएलएम में चरणबद्ध कार्यान्वयन का दृष्टिकोण अपनाया जाता है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी जिलों और ब्लॉकों में एनआरएलएम का विस्तार हो जाएगा ।

"गहन ब्लॉक", ऐसे ब्लॉक जहां एनआरएलएम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, में पूरी संख्या में प्रशिक्षित पेशेवर स्टाफ होंगे और इनमें सर्वव्यापी एवं गहन सामाजिक तथा वित्तीय समावेशन, आजीविका, साझेदारी आदि क्रियाकलापों की पूरी श्रृंखला शामिल होगी । तथापि, शेष बचे ब्लॉकों या गैर-गहन ब्लॉकों में क्रियाकलापों का विस्तार एवं गहनता सीमित हो सकती है । इन ब्लॉकों के लिए परिव्यय अधिक से अधिक एसजीएसवाई के अंतर्गत इन ब्लॉकों के लिए राज्य औसत आबंटन के बराबर होगा ।

20. एनआरएलएम को अपनानाः एनआरएलएम के औपचारिक रूप से शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनआरएलएम को लागू करना होगा । इसके पश्चात एसजीएसवाई के अंतर्गत आगे किसी भी तरह के वित्तपोषण को रोक दिया जाएगा ।

21. एनआरएलएम के समक्ष एजेंडाः एनआरएलएम ने देश में 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6.0 लाख गांवों में 7.0 करोड़ बीपीएल परिवारों को उनके स्वतः प्रबंधित एसएचजी, तथा उनके परिसंघों और आजीविका क्रियाकलापों में सहायता देकर उन्हें एकजुट करने का एजेंडा निर्धारित किया है । एनआरएलएम की दीर्घावधिक समर्पित संवेदनशील सहायता उन्हें प्राप्त होगी तथा गरीबी से निकलने के उनके सभी प्रयासों में उन्हें सुविधा सहायता दी जाएगी । इसके अलावा, निर्धनों को उनके अधिकार, हक और जनसेवाएं, परिवर्तित जोखिम और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक सूचकांक दिलाने में मदद की जाएगी ।

अध्याय - 1
सामाजिक समावेशन, एकजुटता और संस्थान

निर्धनों को उनकी"अपनी संस्थाएं" बनाने के लिए एकजूट करना वृहत पैमाने पर गरीबी उपशमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त और पहल है । एनआरएलएम सभी निर्धन परिवारों (महिलाओं) को निर्धनों की समूह संस्थाओं में संगठित करेगा जिससे उनके विचारों को सुना एवं समझा जा सकेगा तथा उन्हें संसाधन मुहैया हो पाएगा । 'निर्धनों के' और 'निर्धनों के लिए' ये मंच स्थानीय स्व-शासन, सार्वजनिक सुविधा प्रदाताओं, बैंकों, निजी क्षेत्र और संस्थान की अन्य मुख्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि निर्धनों को सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं आसानी से मिल सकें ।

सामाजिक समावेशन और सर्वसामान्य सामाजिक एकजुटताः यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी निर्धन परिवार बचा न रह जाए, एनआरएलएम निर्धारित किए गए सभी बीपीएल परिवारों को सुचारू रूप से कारगर और स्वतः प्रबंधित संस्थानों में सामाजिक रूप से शामिल/एकजुट करने के लिए विभेदक कार्यनीतियों का इस्तेमाल करेगा जिसमें अनु. जातियों, अनु. जनजातियों जैसे अधिक उपेक्षित वर्गों, खासकर उपेक्षित जनजातीय समूहों, एकल महिला और महिला प्रमुख परिवारों, विकलांगों, भूमिहीनों, पलायन किए गए श्रमिकों, और अलग-अलग पड़े क्षेत्रों में रहने वाले इक्का-दुक्का समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । यह भागीदारीपूर्ण उपेक्षनीयता मूल्यांकन और रैंकिंग के जरिए बीपीएल में से अत्यंत निर्धन और उपेक्षितों का निर्धारण करेगा । एकजुटता सबसे पहले उनसे ही शुरू होगी । संतोषप्रद सामुदायिक तत्परता और एकजुटता के विभिन्न स्तरों की उपलब्धियों तथा भागीदारीपूर्ण तरीके से बनाई एवं जांची गई अर्हता के साथ एकजुटता प्रयासों में प्रगति होगी । मौजूदा संस्थान, उनके प्रमुख, स्टाफ और सामुदायिक रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) समावेशन और एकजुटता की प्रक्रिया में मदद करेंगे ।

निर्धनों के संस्थागत मंच को बढ़ावा देनाः आमतौर पर 10-20 व्यक्तियों (दुर्गम क्षेत्रों में 5-20 व्यक्ति) का एक स्व-सहायता समूह एनआरएलएम संस्थागत डिजाइन का प्रमुख निर्माण खंड है । एनआरएलएम सिर्फ महिला सदस्यता वाले स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देगा । मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जरिए परिवार के सभी सदस्यों तक पहुंचना है । देशभर में और वैश्विक रूप से वृहत पैमाने पर प्राप्त अनुभव से यह प्रमुख सीख मिली है । निर्धनों की आजीविका के लिए निधियों का मुख्य स्त्रोत बैंकों से मिल सकता है । देश के बैंक महिलाओं के एसएचजी को ऋण देने के पक्ष में हैं । एसएचजी स्व-सहायता, पारस्परिक सहयोग तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सामूहिक क्रियाकलाप की दृष्टि से महिला सदस्यों को अवसर देने के प्रयोजन को पूरा करता है । यह बचत को बढ़ावा देता है, स्वयं की निधियों का सृजन करता है और ऋण से मुक्ति एवं आजीविका के लिए ऋण उपलब्ध कराने सहित वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने वाली स्थानीय वित्तीय संस्थान बन जाती है । सफल एसएचजी कार्यनीति के कुछ प्रमुख अवयव हैं- (i) स्व-निर्धारित/स्वैच्छिक समूह सदस्यता और समूह मानदंड; (ii) समूह सदस्यता में एकजुटता (स्व-चयनित प्रक्रिया के जरिए); (iii) समूह द्वारा नियत बचत और आपसी लेन-देन का मानदंड; (iv) निर्वाध उपयोग के लिए अपनी बचत से आपस में शुरूआती लेन-देन; (v) सहायक सेवाएं (प्रशिक्षण, बुक-कीपिंग आदि जैसे) मुहैया कराने के लिए सामाजिक पूंजी; (vi) सदस्यों की ऋण संबंधी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पूंजी संवर्धन के लिए बैंकों से ऋण और परिक्रमी निधि; और (vii) एसएचजी का उच्च श्रेणी का परिसंघ ।

एसएचजी की निर्देशात्मक विकास उपलब्धियां हैं -

- निर्माण से पूर्व (2-3 माह): प्रोफाइलिंग और सुभेद्यता निर्धारण; प्रारंभिक वार्ता
- निर्माण (6 माह): पंचसूत्र (नियमित बैठक; नियमित बचत; नियमित आपसी लेनदेन; समय पर पुनर्भुगतान; और अद्यतन बहीखाता) बनाना, मानदंड तैयार करना और कार्यान्वित करना, माइक्रो इनवेस्टमेंट प्लान (एमआईपी) बनाना, नेतृत्व विकास
- संपर्क (6-24 माह): क्षमता निर्माण, एमआईपी, बैंकों के साथ संपर्क और प्राथमिक परिसंघों का गठन करना ।
- बाद में (दूसरे वर्ष से): विजन तैयार करना/प्लान, आजीविका, नए उत्पाद, सामाजिक पूंजी ।

पहले से विद्यमान एसएचजी और परिसंघों का समावेशनः एनआरएलएम मौजूदा एसएचजी और एसएचजी परिसंघों, जिनमें से अधिकांश सदस्य बीपीएल परिवारों से हैं (70% और अधिक) की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्हें सहायता देगी । इससे इन मौजूदा समूहों और परिसंघों की गुणवत्ता की ग्रेडिंग की प्रक्रियाएं तैयार होंगी । ग्रेडिंग से संस्थाओं का श्रेणियों में निर्धारण हो पाएगा, उदाहरणार्थ तीन श्रेणियों में (i) बुनियादी मानदंडों को पूरा करने; (ii) प्रशिक्षित किया जा सकता है, और (iii) इस पर कार्य नहीं किया जा सकता है । एनआरएनएम बढ़ावा देने वाली संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों तथा अन्य लाइन विभागों का मूल्यांकन करने के लिए तौर-तरीके भी तैयार करेगा । एनआरएलएम कवरेज में पूर्णता लाने के लिए उनके साथ भागीदारी भी करेगा । परस्पर रूप से सहमत कार्यनीति बनाई जाएगी ताकि समय और संसाधनों का निवेश बरबाद न हो जाए और एनआरएलएम प्रक्रियाओं को अच्छी शुरूआत मिल सके ।

सामूहिक क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर परिसंघों का निर्माणः सामूहिक कार्रवाई, बेहतर तालमेल, तोल मोल की शक्ति, उत्पादन वृद्धि के जरिए लागत में कमी और बेहतर संपर्क के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्धनों की संस्थाएं बनाई जाएंगी एवं इन्हें बहाल रखा जाएगा । अनुक्रम सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर परिसंघ के पास स्वयं का उद्देश्य, कार्य और पहचान होगी । ये संस्थाएं स्वतंत्र होंगी, फिर भी मूल रूप से एक दूसरे पर आश्रित होंगी ।

राज्य संघबद्ध तर्क उत्कृष्ट कार्यों और अनुभव के आधार पर ग्राम, ग्राम पंचायत, समूह ब्लॉक आदि में परिसंघों के विभिन्न स्तरों और स्थानों का निर्धारण करेंगे । ग्राम या पंचायत स्तर पर प्राथमिक परिसंघ 10-20 एसएचजी को आपस में बांधे रख पाएंगे (जनजातीय क्षेत्रों या विरल आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 5-20 एसएचजी) । इसकी जिम्मेवारियों में (i) सभी बचे हुए निर्धनों को एसएचजी दायरे में लाना; (ii) एसएचजी को प्रशिक्षण, बुक-कीपिंग आदि जैसी सहायक सेवाएं मुहैया कराना; (iii) उच्च श्रेणी की वित्तीय और आजीविका सेवाएं मुहैया कराना; और (iv) जनसेवाएं एवं हकदारी दिलाने में मदद करना ।

समावेशी भागीदारीपूर्ण और जवाबदेह परिसंघ बनाना एक गहन प्रक्रिया है। इसमें घटक इकाइयों की संवेदनशीलता और सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है । परिसंघ अपने स्वयं की संघीय मदों वाली विधिक सत्ता होगी जो विभिन्न

सामाजिक, वित्तीय और/या व्यावसायिक कार्य करेगी । सामान्य निकाय की समग्र जवाबदेही के साथ, कार्यकारी समिति और विभिन्न उप-समितियां अपने स्टाफ, सामुदायिक सुविधा प्रदाताओं, पेशेवरों और/या अन्य मानव संसाधनों के जरिए परिसंघों की योजनाएं कार्यान्वित करेंगी । परिसंघों को जारी रखने के लिए अच्छे शासन, आवधिक समीक्षा, नियोजन और निगरानी, खाता और रिकार्ड कीपिंग, आंतरिक, सांविधिक और सामाजिक लेखा परीक्षा आदि जारी रहेगी । वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के अलावा, माइक्रो प्लानिंग, व्यावसायिक और विपणन संपर्क में इनकी क्षमताएं सृजित की जाएंगी ।

आमतौर पर परिसंघों की वित्तीय सेवाएं केवल सदस्यों और उनके परिवारों तक ही सीमित होंगी । असहाय, गंभीर बीमारी/एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों + विकलांगों, अकेली महिलाओं आदि जैसे लाभ से वंचित व्यक्तियों के मामले में, गैर-सदस्यों को भी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी । गैर-सदस्यों को तकनीकी सेवाएं (डेयरी, कौशल प्रशिक्षण, और युवाओं के नियोजन, विपणन आदि) भी दी जाएं ।

एनआरएलएम में क्षमता निर्माण और परिसंघों की स्टाफ संबंधी लागत, उनके प्रमुखों, पेशेवर स्टाफ, सामुदायिक पेशेवरों और अन्य सुविधा-प्रदाताओं/रिसोर्स पर्सनों का तब तक प्रावधान किया जाएगा जब तक कि वे आत्मनिर्भर नहीं बन जाते । इसी दौरान, इन परिसंघों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका पालन-पोषण किया जाएगा । इन परिसंघों को 3-5 वर्षों में निर्माण पूर्व, निर्माण, कार्य, विकास और स्थायित्व के पांच चरणों में विकसित किया जाएगा ।

परिसंघ एनआरएलएम कार्यनीति की सफलता की कुंजी है । जैसे-जैसे उनकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, वे निर्धनों के लिए सहायक संगठन बन जाएंगे और बाह्य सहायक संरचना के लिए राज्यों की संदर्श योजनाओं में स्पष्ट रूप से 'एक्जिट स्ट्रेटेजी' प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

आजीविका समूह जैसी विशिष्ट संस्थाएं: एनआरएलएम उत्पादन वृद्धि के जरिए लागत में कमी करने, पूर्वापरक संपर्क, सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट आजीविका, संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करेगा । वे पूर्वापरक संपर्कों के साथ उत्पादन-वितरण मूल्य-श्रृंखला में अंतर को दूर करेंगे और सह-उत्पादन में शामिल होंगे तथा अंतिम छोर तक आजीविका सेवाओं की सुपुर्दगी करेंगे । ये समूह खेतों में खेती, पशुधन, वाणिकी, मत्स्य क्षेत्र, गैर-कृषि और सेवा क्षेत्रों में हो सकते हैं ।

सामाजिक पूंजी सृजित करना: एनआरएलएम निर्धन समुदायों की सहायता करने के लिए "सामाजिक पूंजी" अर्थात निर्धनों की संस्थाओं, उनके सदस्यों और कार्यालय-धारकों, सामुदायिक रिसोर्स पर्सनों, सामुदायिक पेशेवरों (बुक कीपर्स, लेखाकार, सामुदायिक प्रणेता/सुविधा प्रदाता, बैंकों में कस्टमर रिलेशनशिप प्रबंधक आदि) का एक बड़ा पूल बनाने में निवेश करेगा । आपूर्ति संबंधी प्रक्रियाओं से सेवाओं अर्थात सामुदायिक कृषि विस्तार कर्मी, पैरा-वेट्स, ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी आदि की 'बेहतर उपलब्धता' सुनिश्चित होगी । मांग संबंधी प्रक्रियाओं से समूहन (अर्थात् वस्तु प्रापण केंद्रों और दुग्ध एकत्रीकरण केंद्रों, बैंक मित्रों आदि की सहायता करने वाला रिसोर्स पर्सन) के जरिए सेवाओं की 'उन्नत पंहुच' सुनिश्चित होगी ।

एनआरएलएम प्रक्रियाओं के जरिए सृजित सामाजिक पूंजी एनआरएलएम को आगे बढ़ाने और इसे जारी रखने के लिए

महत्वपूर्ण हैं । एनआरएलएम के अंतर्गत गरीबी उपशमन कार्यनीति केवल तभी सफल रहेगी जब इसे पूरी तरह स्वयं निर्धनों द्वारा संचालित किया जाए । जहां तक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का संबंध है, सामुदायिक रिसोर्स पर्सन एनआरएलएम के 'गतियमान वाहक' हैं । जहां तक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नियत क्षेत्र में उसे जारी रखने का संबंध है, एसएचजी के परिसंघ और सामुदायिक पेशेवर 'स्थिर वाहक' हैं ।

निर्धनों की स्व-प्रबंधित आत्मनिर्भर संस्थाएं बनाने वाली प्रक्रियाएं एवं तंत्रः प्रशिक्षण, सहायता और व्यवस्थित मार्गदर्शन के जरिए, एनआरएलएम संस्थाओं में सदस्यों को स्वामित्व एवं नियंत्रण प्रदान करेगा । यह प्रत्येक स्तर पर सदस्यों, और कार्यालय पदाधिकारियों, सामुदायिक रिसोर्स पर्सनों तथा सामुदायिक पेशेवरों की क्षमताओं और सक्षमता का निर्माण करेगा । यह सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करेगा । एनआरएलएम सहायक संरचना निर्धनों की संस्थाओं की मदद करेगी और इनका पालन पोषण करेगी ताकि वे कुछ समय में सही मायने में स्वतंत्र, स्व-प्रबंधित और आत्मनिर्भर बन सकें ।

इस प्रकार बाह्य समर्पित सहायक संरचना - विभिन्न स्तरों पर मिशन संरचना और गैर-सरकारी संगठन तथा अन्य सीएसओ- समुदाय की स्वामित्व वाली आंतरिक सहायक संरचना-निर्धनों की संस्थाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी । प्रारंभ से ही बाह्य सहायक संरचना को बहाल करने से यह संरचना निर्धनों की संस्थाओं के उद्भव का पालन-पोषण करेगी ताकि वे आंतरिक सहायक संरचना बन जाएं । चूंकि वे सभी प्रक्रियाओं और सभी स्तरों पर अधिक से अधिक जिम्मेवारी उठाते हैं, इसलिए विदेशी सहायक संरचना की भूमिका कम करनी या बदलनी होगी । एनआरएलएम विभिन्न स्तरों पर इस प्रक्रिया में मदद करेगा ।

समुदाय और स्टाफ का क्षमता निर्माणः एनआरएलएम में निर्धनों की संस्थाओं, उनके प्रमुखों, उनके सामुदायिक सुविधा प्रदाताओं और रिसोर्स पर्सनों की निरंतर क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है । सामाजिक, वित्तीय और आजीविका समावेशन में प्रशिक्षण के अलावा, सहायक संरचनाओं में स्टाफों को एनआरएलएम कोर मूल्यों और सिद्धातों से परिचित कराने के लिए अत्यंत गहन प्रशिक्षण देने की जरूरत है । पंचायती राज संस्थान सहित अन्य सभी स्टेकहोल्डरों को संवेदनशील बनाना और उन्मुखीकरण निर्धनों की जरूरतों के प्रति होना चाहिए और इसे अति निर्धन का संदेश होना आवश्यक है ।क्षमता निर्माण में शामिल होंगे; आवश्यकता मूल्यांकन; बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम और घटनाक्रम; क्षमता विकास इकाइयों की स्थापना और उन्हें शामिल करना तथा विभिन्न स्तरों पर रिसोर्स एजेंसियां; काम और सहायता के जरिए शिक्षण को आसान बनाने के लिए प्रायोगिक एवं निदर्शन स्थल; प्रदर्शन दौरा; तथा सर्वश्रेष्ठ रिसोर्स पर्सनों आदि के जरिए अनुभवों का आदान प्रदान आदि । ई-लर्निंग शिक्षा, स्वतः शिक्षण और जन शिक्षण प्रक्रियाएं क्षमता निर्माण का हिस्सा भी होंगी ।

संस्थाओं के प्रबंधन और इनमें भाग लेने के लिए ज्ञान, कौशल और साधन के अलावा, सदस्यों को उनकी मौजूदा एवं नवीन आजीविकाओं को बेहतर बनाने के लिए सरल कौशल और आजीविका संबंधी कौशल उपलब्ध कराए जाएंगे ।

ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न प्रक्रियाओं में, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एनआरएलएम गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सीएसओ के साथ साझेदारी करेगा । इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा पालन पोषण किए जा रहे निर्धन महिलाओं के मौजूदा एसएचजी और उनके परिसंघों को एनआरएलएम द्वारा सहायता भी मुहैया कराई जाएगी।

अध्याय - 2
वित्तीय समावेशन

निर्धनों के लिए स्वीकार्य दरों पर और वांछित मात्रा में और सुविधाजनक पुनर्भुगतान शर्तों पर बार-बार निधियां मिलना महत्वपूर्ण है जिससे वे अपने उपयोग को सुचारू रूप से जारी रख पाएंगे, गरीबी के जाल से बाहर आ पाएंगे और आजीविका परिसंपत्तियों में (अधिग्रहण, नवीकरण और विस्तार) निवेश कर पाएंगे । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन को मुख्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और किफायती तरीके से समाज के सबसे उपेक्षित समूह को उचित वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं मुहैया कराने के रूप में परिभाषित करता है । निर्धनों को बैंकिंग व्यवस्था का प्राथमिकता प्राप्त ग्राहक बनाना तथा बैंक ऋण जुटाना एनआरएलएम वित्तीय समावेशन और निवेश संबंधी कार्यनीति के लिए महत्वपूर्ण है ।

बुनियादी बैंकिंग सेवाएं

बैंकों की भूमिका कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों, एसएचजी और उनके परिसंघों (पंजीकृत/गैर पंजीकृत) के लिए बैंक खाता खोलने से शुरू होगी । बचत, ऋण और प्रेषण सहित पूरी बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाया जाएगा । प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकिंग समितियां (एसएलबीसी) ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जानी वाली प्रक्रिया विधियों और"अपने ग्राहक को जानें" मानदंड पर आम सहमति बनाने में मदद करेगी ।

एसएचजी को वित्तीय सहायता

एनआरएलएम निर्धनों की संस्थाओं के लिए परिक्रामी निधि और पूंजीगत सब्सिडी निधि उपलब्ध कराएगा । इन निधियों के प्रावधान से उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता मजबूत होने और प्रमुख बैंक वित्त पाने की दृष्टि से उनके ट्रेक रिकॉर्ड के सुधरने की संभावना है ।

गैर-गहन ब्लॉकों के लिए, परिक्रामी निधि और सब्सिडी निधि प्राप्त करने के लिए एसएचजी की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, उन्हें ग्रेड-I और ग्रेड- II जैसी ग्रेडिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा ।

एनआरएलएम में विभिन्न प्रकार की सहायता इस प्रकार है -

एसएचजी को परिक्रामी निधि सहायता- एनआरएलएम प्रति एसएचजी कम से कम 10,000 रू. और अधिकतम 15,000 रू. के साथ समूह संचय के रूप में एसएचजी (एसएचजी जिन्हें पहले कभी कोई आरएफ नहीं मिला है) को परिक्रमी निधि सहायता मुहैया कराएगा । उपभोग और प्रारंभिक उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के अलावा, आरएफ सहायता से ऋणों और निधियों के प्रबंधन में एसएचजी की संस्थागत क्षमता भी बढ़ेगी । आरएफ प्राप्त करने के लिए एसएचजी की पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं: -

- कम से कम पिछले 6 महीनों से एसएचजी को सक्रिय रूप से मौजूद होना चाहिए ।
- एसएचजी को 'पंचसूत्र' का निष्पादन करना चाहिए अर्थात् नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित रूप से आपसी लेन-देन, समय पर भुगतान और अद्यतन बही खाते ।
- पंचसूत्र" के निष्पादन के आधार पर ग्रेड-I पार करना चाहिए
- गहन ब्लॉकों में, 'पंचसूत्र' के अलावा, एसएचजी को माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान (एमआईपी) तैयार करने में प्रशिक्षण मिलना चाहिए ।

एमआईपी नियोजन और मूल्यांकन की अत्यंत सहभागितापूर्ण प्रक्रिया है । यह पुनरावृत्तीय है । एसएचजी आवधिक रूप से एमआईपी प्रक्रिया से गुजरेंगे ।इसमें निम्नलिखित शामिल हैः

- परिवार के सदस्यों के परामर्श से तैयार की गई पारिवारिक योजनाएं
- एसएचजी द्वारा पारिवारिक योजनाओं का मूल्यांकन
- सदस्य की सुभेद्यता के आधार पर प्राथमिकता; और
- आकस्मिकता और/या जरूरत के आधार पर प्राथमिकता ।

जैसे-जैसे ऋण की मात्रा बढ़ती जाएगी, समूह नियोजन और कार्यान्वयन प्रक्रिया सुदृढ़ और सक्रिय होती जाएगी। धीरे-धीरे समूह लाभकारी और उपभोग के प्रयोजनार्थ ऋण, ऋणों के उपयोग के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा, पुनर्भुगतान की निगरानी और ऋण पुनर्भुगतान के पुनर्ग्रकण के लिए अपना मानदंड तैयार करेंगे । इस प्रकार एसएचजी की क्षमता निर्माण योजना से एमआईपी संबंधी प्रशिक्षणों के अलावा निश्चित रूप से वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक शिक्षा संबंधी जरूरतें बढ़ेंगी ।

एनआरएलएम निर्धनों की संस्थाओं में बचत और अन्य निधियों को जमा करने और इनके अवरोधन पर बल देता है। इस प्रकार एनआरएलएम को बचत/स्वयं की निधियां संचित करने के प्रयोनार्थ संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का रास्ता मिलेगा।

गैर-गहन ब्लॉकों में, गुणवत्ता मानदंड पर एसएचजी की ग्रेडिंग की मौजूदा व्यवस्था का अनुपालन जारी रहेगा ।

गहन ब्लॉकों में पूंजीगत सब्सिडी सब्सिडी निधि : ऐसी संभावना है कि गांव में सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक वर्ष के भीतर गहन ब्लॉकों में प्राथमिक परिसंघ बन जाएंगे । समूह की गुणवत्ता, उनकी बचतों और आंतरिक लेनेदेनों के प्रबंधन में उनके ट्रेक रिकॉर्ड के आधार पर और उनकी माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान के आधार पर एसएचजी को पूंजीगत सब्सिडी (सीएस) मुहैया कराई जाएगी । सीएस मुहैया कराने के लिए अत्यंत निर्धनों और सर्वाधिक अपेक्षित समूहों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाएगा ।

प्राथमिक ग्रामीण परिसंघ बन जाने के बाद परिसंघ के जरिए एसएचजी को सीएस निधियां दी जाएंगी, जहां एसएचजी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं । एसएचजी सदस्यों को इस वाबत एक प्रस्ताव पारित करना होगा । यह निधि उत्प्रेरक पूंजी के रूप में कार्य करेगी और परिसंघ को इस बात की छूट होगी कि वे सदस्य समूहों की सहमति से विभिन्न जरूरतों के लिए निधियां आवंटित करें । इस निधि को एक बड़े हिस्से का उपयोग एसएचजी को आगे उधार देने के लिए किया जाएगा ताकि वे अपने सदस्यों की आजीविकाओं और अन्य अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दे सके । सीएस प्राप्त करने के लिए परिसंघ (जिन्हें किसी अन्य सरकारी स्रोत से पहले ऐसी सहायता नहीं मिली है) की पात्रता शर्तें इसे प्रकार हैं :-

- बैंक में बचत खाता के साथ प्राथमिक परिसंघ कम से कम 6 महीने से सक्रिय होना चाहिए; और शासी व्यवस्था कार्यालयधारकों के रूप में हो तथा कार्यकारी समितियां बनाई गई हों और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया हो ।
- मानक खाता और एक प्रशिक्षित बुक कीपर मौजूद होना चाहिए ।
- पात्र एसएचजी के लिए एमआईपी बना ली गई हो, और
- कम से कम एक तिहाई समूह सदस्यों ने बैंकों से ऋण लिया हो और इनमें से कम से कम 90% लोगों ने ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान किया हो या बैंकों से यह आश्वासन दिया गया हो कि एक निर्धारित समयावधि के भीतर अच्छे प्रबंधन सिद्धांतों का पालन करने वाले एसएचजी को निधियां दी जाएंगी ।

कुछ राज्यों में, दूसरे स्तर के एसएचजी परिसंघ भी बनाए गए हैं । ये निधियां प्रदान करने के लिए उन पर भी विचार किया जा सकता है यदि वे सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए हों और प्राथमिक परिसंघों के एसएचजी सदस्य इस समझौते के लिए लिखित रूप से अपनी सहमति देते हैं ।

किसी परिसंघ के लिए निधियों की जरूरतें निर्धारित करने के लिए मुख्य मार्गदर्शन सिद्धांत इस प्रकार हो सकते हैं: -

- बीपीएल एसएचजी में से सबसे अधिक उपेक्षित एसएचजी की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम जरूरते;
- सदस्य एसएचजी को वित्त पोषित करने के लिए बैंकों की प्रतिक्रिया ।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा ऋण और स्वास्थ्य सुरक्षा ऋण की जरूरत; तथा
- प्राथमिक परिसंघ की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित राशि ।

प्राथमिक परिसंघों को 3-5 वर्षीय योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें सदस्य एसएचजी के लिए और साथ ही सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित निवेशों को दर्शाया गया हो । निधियों के

स्रोतों - अपनी बचत, बैंक ऋण और सीएस - को दर्शाया जाएगा । सीएस के बढ़ते हुए प्रभाव के संबंध में परिसंघ की प्रगति मापी जा सकती है ।

सीएस निधियां मुख्य रूप से निर्धनों की संस्थाओं को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए तथा निर्धनों की आजीविका में निवेश को तीव्र करने के लिए होगी । इससे एसएचजी को ट्रेक रिकार्ड बनाने में मदद मिलेगी जिससे वे बैंकों से मुख्य वित्तपोषण प्राप्त कर पाएंगे । सीएस अपनी अन्य निधियों के साथ बारंबार बैंकों से मिलने वाले वित्त-पोषण को बढ़ाना है । जब बैंक एसएचजी की जरूरतों पर प्रभावी रूप से ध्यान देना शुरू कर देते हैं तब इस निधि का उपयोग निर्धनों की आजीविका को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सामूहिक क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है । इस प्रकार यह निर्धनों की संस्थाओं के लिए पूंजीगत रिसोर्स / निधि संचय बन जाएगी ।

गैर-गहन ब्लॉकों में पूंजीगत सब्सिडी निधि : एसएचजी परिसंघों की गैर-मौजूदगी में सीएस निधियां सीधे एसएचजी को मिल जाएंगी और सीएस का उपयोग प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के प्रति उनकी विश्वसनीयता दर्शाने तथा सतत आधार पर ऋण की अनेक किस्तें देने में उनका विश्वास बनाने के लिए किया जा सकता है । इस प्रकार सीएस निधि बैंक ऋण से जुड़ जाती है और यह निधि निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले एसएचजी को रिलीज की जाएगी :

- कम से कम 12 महीने से सक्रिय हो,
- परिक्रामी निधि प्राप्ति की बाद कम से कम 6 महीने बीत गए हों,
- वित्त बैंकों से संतोषप्रद रैंकिंग मिली हो,
- बैंक संपर्क से कम से कम एक बार ऋण प्राप्त किया हो और शीघ्र ही इसका पुनर्भुगतान किया हो,
- दूसरी ग्रेडिंग हासिल की हो,
- पहले सीएस प्राप्त नहीं किया हो, और
- शुरू किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए सुस्पष्ट प्रस्ताव बनाए गए हों ।

एसएचजी की दूसरी ग्रेडिंग के प्रयोजनार्थ, राज्य खुद का पारदर्शी ग्रेडिंग मानदंड और प्रक्रिया बनाएंगे ।

बैंक एसएचजी बैंक संपर्क कार्यक्रम के वित्तपोषण मानदंड का अनुपालन करेंगे । तथापि, बैंक कम से कम 1: 2 का सब्सिडी-ऋण अनुपात रखेंगे । चूंकि उपलब्ध सीएस की मात्रा के आधार पर ब्लॉक में पात्र बीपीएल एसएचजी की संख्या काफी अधिक होगी, इसलिए उन्हें चुनने / प्राथमिकता क्रम तय करने के लिए कुछ मानदण्डों का उपयोग किया जासकता है । निर्देशात्मक मानदंड में शामिल हैं : -

- आयु और एसएचजी की ग्रेडिंग
- एसएचजी की व्यवहार्यता
- सभी गांवों में इक्विटी
- ऋण : सब्सिडी अनुपात – अनुपात जितना अधिक होगा, पात्रता उतनी बेहतर बनेगी; और
- एनजीओ और अन्य सीएसओ के जरिए एसएचजी को मौके पर उपलब्ध सहायता ।

चरणबद्ध प्लान के अनुसार जैसे ही कोई ब्लॉक गहन ब्लॉक बन जाता है, गहन ब्लॉकों के लिए प्रयुक्त पद्धति लागू की जाएगी ।

किसी भी परिस्थिति में बीपीएल एसएचजी के लिए तथा एसएचजी में व्यक्तियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा नहीं बढ़ेगी । इसमें आगे की अधिकतम सीमा लगाई जा सकती है क्योंकि सीएस निधि सीमित है।

एसएचजी के लिए बैंक वित्त पोषण: बैंक वित्त-पोषण दो रूपों में होगा – एसएचजी और उनके परिसंघों के लिए नाबार्ड का एसएचजी बैंक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त-पोषण; और समूह आधार पर विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापों के लिए एसएचजी या उनके परिसंघों का वित्त-पोषण । बैंक वित्त-पोषण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

क. इसे मुख्य व्यावसायिक अवसर मानने वाले बैंक व्यावसायिक ग्राहक के रूप में एसएचजी को देखेंगे । बैंक एसएचजी में व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाएंगे और सतत आधार पर ऋण सहायता देंगे ।

ख. बैंक एसएचजी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन साधन के रूप में नाबार्ड द्वारा बनाई गई रेटिंग इंडेक्स को अपनाएंगे ।

- एसएचजी की पात्रता, प्रत्येक रिपीट लोन के साथ ऋण की मात्रा को बढ़ाने, ऋण की अवधि, एक समान रेटिंग मानदंड, ऋण प्रलेखन आदि जैसे मानदण्डों पर विभिन्न सहभागी बैंकों में आपसी सहमति बनाई जाएगी ।

व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

असाधारण असंभाव्यता के मामले में, जहां संगठित होना संभव नहीं है, गांव में निर्धनों की किसी मौजूदा संख्या के जरिए किसी भी व्यक्ति को लाभ / सहायता देने पर विचार किया जा सकता है । यह संस्थान या पीआरआई सर्वाधिक वांछित लाभार्थियों का निर्धारण एवं पुष्टि करने और वित्त पोषण के लिए व्यावसायिक योजना का मूल्य निर्धारित करने की जिम्मेवारी लेगी । अधिक उम्मीदवारों के मामले में, उनमें से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जाएगा । वैयक्तिक लाभार्थी के सीएस सामान्य श्रेणी में अधिकतम 15,000 रू. और अ.जा. /

अ.ज.जा श्रेणी में 20,000 रू. होगी । कुल मिलाकर एनआरएलएम / एसआरएलएम वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त कुल वैयक्तिक लाभार्थियों में एक निर्धारित थ्रेसोल्ड रखेगा अर्थात अ.जा. 50%, अल्पसंख्यक - 15%, महिला - 50% और विकलांग व्यक्ति - 3% ।

ब्याज सब्सिडी

ग्रामीण निर्धनों को स्वीकार्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने और उनके निवेशों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए एनआरएलएम ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगा । बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज और ऋण का नियमित रूप से पुनर्भुगतान करने वाले बीपीएल एसएचजी के लिए मुख्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सभी ऋणों पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर के बीच यही अंतर है । निष्पादन से जुड़ी इस ब्याज सब्सिडी से संपूर्ण ऋण चक्र में बैंकों में दीर्घकालिक अवधि के लिए नियुक्ति की जा सकेगी । यह संस्थाओं और उनकी व्यावसायिक योजनाओं की गुणवत्ता पर आधारित ऋण देने के पक्ष में बैंकों में आबंटन आधारित वित्तपोषण के तर्क को भी रद्द कर देगा और इससे एसएचजी को रिपीट वित्तपोषण मिलने लगेगा तथा बैंकों और एसएचजी के बीच दीर्घकालिक संबंध बन जाएगा । यह सब्सिडी प्रत्येक बीपीएल परिवार को तब तक उपलब्ध होगी जब तक अनेक किस्तों में उनकी संचयी ऋण राशि कुल मिलाकर एक लाख रू. तक नहीं पहुँच जाती । जब कोई समूह एक साथ पूंजीगत सब्सिडी और बैंक ऋण प्राप्त करता है तब ब्याज सब्सिडी लागू नहीं होती । तथापि, जब कोई समूह पूंजीगत सब्सिडी के बिना रिपीट लोन लेता है तब ब्याज सब्सिडी लागू रहती है । ब्याज सब्सिडी की आवधिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते लाभार्थी नियमित रूप से ऋण का पुनर्भुगतान करता रहे ।

निर्धनों के लिए बीमा सेवाएं

एनआरएलएम लघु-बीमा सेवाओं की सर्वव्यापी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से निर्धनों और उपेक्षित परिवारों के जीवन, स्वास्थ्य और परिसंपत्तियों को कवर करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ काम करेगा । इसमें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछेक बीमा योजनाओं अर्थात ' आम आदमी बीमा योजना' , 'जनश्री बीमा योजना' , ' राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना' और कृषि एवं पशुधन बीमा योजनाओं के साथ तालमेल करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

समन्वय प्रक्रिया

ऋण वितरण तथा उसके उपयोग की निगरानी के लिए विभिन्न लाइन विभागों, बैंकों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र बैंकों, एनजीओ तथा अन्य सीएसओ की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है । उपयुक्त समन्वय के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित समितियां गठित की जा सकती हैं : -

केन्द्रीय स्तर : सचिव (ग्रा0वि0), ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति 1 जिसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, वाणिज्यिक

बैंकों तथा राज्यों के ग्रामीण विकास सचिव आदि शामिल हैं । संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (एनआरएलएम) इसके सदस्य-सचिव हैं । समिति की प्रत्येक छह महीने में एक बैठक निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने के लिए की जाएगी : -

1. ऋण सहायता सहित वास्तविक, वित्तीय तथा गुणात्मक संदर्भों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा
2. एनआरएलएम संबंधी सहायता सेवाओं के लिए लिंकेज की समीक्षा
3. समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करना
4. राज्य सरकारों तथा बैंकरों के साथ सतत रूप से बातचीत हेतु मंच उपलब्ध कराना और
5. ऋण व्यवस्था की समीक्षा करना और परिवर्तन तथा सुधार सुझाना

राज्य स्तर : एसएचजी बैंक लिंकेज तथा एनआरएलएम कार्यकलापों में वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी द्वारा एक उप समिति गठित की जाएगी । इस उप समिति के कार्यों में वित्तीय समावेशन तथा ऋण लिंकेज की आयोजना, समन्वय, निगरानी तथा समीक्षा शामिल है । इस उप समिति की कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बैठक अवश्य की जाएगी ।

जिला स्तर : जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय (ऋण समीक्षा) समन्वय समिति (डीएलआरसी/डीएलसीसी) एनआरएलएम कार्यकलापों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और एसएचजी, एसएचजी परिसंघों तथा आजीविका समूहों को ऋण की आपूर्ति में बाधाओं को दूर करेगी । इस समिति की कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बैठक निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए अवश्य की जाएगी : -

1. वास्तविक तथा वित्तीय संदर्भों में समग्र प्रगति की निगरानी तथा समीक्षा करना
2. अन्तः एजेंसी मतभेदों को दूर करना तथा एसएलबीसी के विचारार्थ मदें तैयार करना
3. प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और
4. सुधारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए बैंक-वार, ब्लॉक-वार वसूली की निगरानी करना ।

उप जिला स्तर पर, संयुक्त ब्लॉक स्तरीय परामर्श समितियां एसएचजी - बैंक लिंकेज एवं एनआरएलएम की समीक्षा करेंगी । जिला एवं उप जिला मिशन यूनिट सदस्य, अन्य ब्लॉक स्तरीय विकास अधिकारी, बैंक शाखा प्रबंधक, एसएचजी प्रतिनिधि, एसएचजी-बैंक लिंकेज समिति (समितियों) के चयनित सदस्य, और/अथवा एसएचजी परिसंघ के पदाधिकारी तथा ब्लॉक के अंतर्गत आजीविका संगठनों के प्रतिनिधि इन समितियों की बैठकों में भाग लेंगे ।

वित्तीय सेवाओं को गरीबों के लिए उपयोगी बनाना

एनआरएलएम के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्रमुख बैंकों तथा बीमा कम्पनियों के साथ नीतिगत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी । इसके द्वारा बैंकों/बीमा कम्पनियों तथा गरीबों के लिए परस्पर उपयोगी संबंध स्थापित करने हेतु अनुकूल स्थितियां उपलब्ध करायी जाएंगी । इसमें ग्रामीण वित्तपोषण के संदर्भ में मांग एवं आपूर्ति संबंधी विविध कार्यकलाप शामिल होंगे । इनमें से कुछ इस प्रकार हैं : -

(क) सभी एसएचजी के क्षमता निर्माण के क्रम में वित्तीय साक्षरता, बचत के संबंध में परामर्श सेवाएं, ऋण तथा बीमा और लघु निवेश आयोजना के संबंध में प्रशिक्षण ।

(ख) ग्राहक संपर्क प्रबंधकों (कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर) (बैंक मित्र, बीमा मित्र) की नियुक्ति के माध्यम से गरीब ग्राहकों को बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा गरीबों के संस्थानों को बैंक लिंकेज तथा ऋणों की वसूली के लिए उप समितियां गठित करने को प्रोत्साहित करना

(ग) बैंकों द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट एवं प्रारंभिक सेवाओं, एसएचजी तथा परिसंघों को ऋणों की निगरानी तथा वसूली के लिए विशिष्टीकृत अग्रणी दल गठित किए जा सकते हैं ।

(घ) गरीबों के संस्थानों के माध्यम से नई बचतें, ऋण, वसूली तथा बीमा उत्पाद

(ङ) सभी गरीबों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ भागीदारी करना, सूचना प्रौद्योगिकी मोबाइल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और गरीबों तथा युवाओं की संस्थाओं को बिजनेस फेसिलिटेटर्स एवं बिजनेस कोरेसपोन्डेंट के रूप में प्रोत्साहित करना ।

(च) कोर बैंकिंग सोल्यूशंस तथा अन्य वित्तीय प्रौद्योगिकियों - अलग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्वाइंट्स एवं बिजनेस प्रोसेसिंग सैल्स का उपयोग करते हुए नई बिजनेस प्रक्रियाओं को अपनाना ।

(छ) सहभागी बैंकों के प्रत्येक नियंत्रण कार्यालय में समीक्षा तथा समन्वय हेतु एनआरएलएम के विशिष्टीकृत प्रकोष्ठ स्थापित करना, ताकि शाखाओं को स्थल पर दिशा-निर्देश दिए जा सकें ।

(ज) गरीबों की संस्थाओं की स्वयं की निधियों में बढ़ोतरी के साथ-साथ गरीबों के लिए आधारभूत बैंकिंग हेतु लागत प्रभावी सार्वजनिक बैंकिंग संरचनाएं ।

(झ) अंतिम स्थिति में बीमा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काल सैन्टर तथा प्रशिक्षित सामुदायिक पेशेवरों (बीमा मित्र) सहित समुदाय आधारित मॉडल्स और

(ञ) ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए वेब पोर्टल

अध्याय - 3
आजीविका

एनआरएलएम के अंतर्गत मुख्य ध्यान कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबों की आजीविका संबंधी मौजूदा कार्य को स्थायी बनाना तथा बढ़ावा देना है। गरीबों का उपभोग संबंधी तरीका उनके हित, उत्पादकता एवं जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित करता है। कार्य संबंधी जोखिम, जीवन चक्र संबंधी जोखिम, उपभोग/उत्पादन के लिए अधिक लागत और कार्य की शोषणात्मक स्थितियां गरीबों को बहुत कमजोर बनाती हैं। इसका सामना करने के लिए गरीब एवं कमजोर परिवार विविध एवं आजीविका संबंधी बहु कार्यनीतियों का अनुसरण करते हैं। इन सभी लोगों को सहायता दी जानी चाहिए।

गरीबों की सर्वाधिक सामान्य आजीविका मजदूरी श्रम, लघु एवं सीमांत भूमि पर खेती अथवा काश्तकारी, पशुपालन, वनोत्पाद एकत्रित करना, मत्स्य पालन आदि है। सर्वाधिक सामान्य गैर-कृषि आजीविका पारंपरिक पेशा- बुनाई, बढ़ईगिरि, लोहारी, कपड़ा धुलाई आदि हैं। गरीब लोग रोजगार के अभाव के समय में नवीन वैकल्पिक आजीविका विकल्पों को भी खोज रहे हैं। गरीब केवल उत्पादक एवं सेवा प्रदाता ही नहीं है। वे उपभोक्ता भी हैं, दैनिक आवश्यकता अपने आजीविका क्रियाकलापों के लिए जानकारी एवं कच्चे माल के उपभोक्ता हैं। इस प्रकार गरीब क्रमशः उपभोग-ऋण विनिमय-मौजूदा आजीविका संवर्द्धन-विविधिकरण से संक्रमण की ओर बढ़ते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, एनआरएलएम प्रत्येक परिवार की आजीविका के संपूर्ण पहलू की जांच करेगा और वैयक्तिक/परिवार स्तर पर अथवा सामूहिक रूप में अथवा दोनों स्तरों पर क्रियाकलापों के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। इस तरह एनआरएलएम के अंतर्गत आजीविका समावेशन के तीन स्तंभ हैं :

* आजीविका संबंधी मौजूदा विकल्पों को सुदृढ़/संवर्द्धित करने एवं उनके विस्तार के जरिए दुर्बलता न्यूनीकरण और आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि, पशुधन मात्स्यिकी वन उत्पाद संग्रहण आदि जैसी मुख्य आजीविका जिससे सामान्यतः सर्वव्यापी रूप से अपनाई जाती है, के अंतर्गत नए अवसरों का उपयोग करना

*रोजगार- रोजगार के लिए कौशल निर्माण करना, और

* उद्यम- स्वनियोजित और उद्यमियों का संपोषण करना (लघु उद्यम)

दुर्बलता न्यूनीकरण

यह मुख्यतः सघन ब्लॉकों के लिए लागू है।

सेवा, सुरक्षा नेट एवं हकदारी उपलब्ध कराना- हकदारी यथा जन वितरण प्रणाली, पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के रूप में बृहद संसाधन अतिरिक्त आय, व्यय पर बचत और संवर्द्धित उपभोग को सुदृढ़ कर सकते हैं। बेहतर उत्तरदायित्व तंत्र के साथ गरीब की संस्था ऐसी सेवाओं एवं हकदारी की विश्वसनीय एवं कुशल सुपुर्दगी के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगी।

खाद्य एवं स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए आवश्यकता आधारित मॉडलः अभाव की स्थिति में भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी आपात व्यय के लिए गरीबों द्वारा ऋण लेने से प्रायः उत्पादक परिसंपत्तियों एवं आजीविका का नुकसान होता है। सघन ब्लॉकों में एनआरएलएम के अंतर्गत प्राथमिक एसएचजी परिसंघ को सहायता दी जाएगी ताकि वे आजीविका परिसंपत्तियों के लिए संसाधनों के अतिरिक्त भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यय का वित्त पोषण करने के लिए समर्पित संसाधन आवंटिक कर सकें। यह सहायता साथ आने वाले स्वसहायता समूहों एवं इसे परिचालित करने के लिए लघु योजनाएं तैयार करने पर आधारित होंगी। गरीब परिवारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अच्छे समय में और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में" स्वास्थ्य जोखिम निधि" में सेपरेट हेल्थ सेविंग करें। सदस्य परिवारों को नाममात्र दर और आसान किस्तों पर ऋण दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा संबंधी मॉडलों में जन वितरण प्रणाली से खाद्य खरीद को वित्त पोषित करना, खुले बाजार से भारी मात्रा में खरीद और वस्तु ऋण के रूप में वितरण करना शामिल है।

ऋण पुनर्संरचनाः एनआरएलएम के अंतर्गत मौजूदा उच्च लागत ऋण संरचना में बदलाव करने और सहगामी शोषणात्मक संबंधों से गरीबों को मुक्त करने के लिए कार्य किया जाएगा। इससे स्वसहायता समूहों के कार्य में उपभोग ऋण प्राप्त करने तथा प्राथमिक एसएचजी परिसंघ एवं बैंकों द्वारा ऋण माफी के लिए एमआईपी के वित्त पोषण में मदद मिलेगी जिससे कि गरीबों की उच्च ऋणग्रस्तता को कम किया जा सकेगा।

अत्यंत निर्धन परिवारों को लघु अनुदान और उदार ऋणः

प्राथमिक परिसंघ निराश्रित, वृद्ध, दुर्बल एवं अपंग जैसे अत्यंत गरीब लोगों को खाद्य एवं स्वास्थ्य संबंधी आपात व्यय को पूरा करने के लिए लघु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए सीएस निधि से विशेष कोष बनाने में सहायता करेगा। इस सहायता राशि को एकमुश्त सहायता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वे अधिकतम प्रभाव के लिए इन लघु अनुदानों को अन्य हकदारी यथा पेंशन, खाद्य सहायता, जन वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा, एनआरईजीएस आदि के साथ मिला सकते हैं।

जब तक परिसंपत्तियों से नकद लाभ मिलना शुरू न हो जाए तब तक इस निधि का उपयोग खाद्य/स्वास्थ्य/कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक परिसंपत्तियां एवं सुरक्षा नेट (लघु अनुदान) अर्जित करने के लिए उदार ऋण को कार्यनीतिगत रूप से सम्मिलित करके अत्यंत गरीब परिवारों (जो स्वसहायता समूहों में अविलंब भागीदारी करने में कठिनाई महसूस करते हैं) के सामाजिक समावेशन के लिए किया जा सकता है। इस तरह अत्यंत गरीब लोग धीरे-धीरे मुख्य कार्यनीति की ओर अग्रसर होते हैं।

यह निधि व्यक्तियों एवं स्वसहायता समूहों के लिए सीएस की सीमा के भीतर स्वसहायता समूहों से परामर्श और तैनाती की आवश्यकता एवं उनके तरीके पर उनकी सहमति के आधार पर सृजित की जाएगी।

आजीविका संवर्द्धन

यह मुख्य रूप से सघन ब्लॉकों के लिए लागू है। एनआरएलएम के अंतर्गत अपने स्वसहायता समूहों एवं परिसंघों के जरिए अलग अलग सदस्यों/परिवारों को आजीविका संबंधी ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, बाजार ज्ञान, जोखिम प्रबंधन, उत्पाद एवं ऋण सहायता प्रदान करेगा।

यह सहायता आय के स्रोत एवं रोजगार, व्यय से बचाव जोखिम प्रबंधन, ज्ञान, कौशल, परिसंपत्तियां एवं अन्य संसाधन संवर्द्धन/ अनुकूलन के क्षेत्र से संबंधित होगी। इसके अंतर्गत गरीबों की संस्थाओं को मदद दी जाएगी ताकि वे सामूहिक खरीद, समूह मूल्य संवर्द्धन और अपने उत्पाद की सामूहिक बिक्री की जांच कर सकें।

गरीबों की स्थायी आजीविका के लिए सामूहिक प्रयास (सीएसएलपी)

सदस्यों को विश्वसनीय, किफायती एवं सस्ता सेवा सुपुर्दगी-ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, साधन, परिसंपत्ति एवं निवेश के लिए स्वसहायता समूहों और उनके परिसंघों में गरीबों के सर्वव्यापी जुटान के लक्ष्य हासिल करने के बाद एनआरएलएम के अंतर्गत गरीबों की मुख्य आजीविका के लिए विशिष्ट आजीविका संस्थाओं एवं सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा।

- उत्पाद और/या मांग/आपूर्ति को एकत्र करने और उत्पादन में वृद्धि के जरिए लागत में कमी करने, पूर्वापरक संपर्क बनाने और बाजार-सामूहिक प्रापण, मूल्य संवर्धन और विपणन आदि पहुंच बनाने के लिए; और
- सामूहिक उत्पादकता संवर्धन, सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, जानकारी और सुविधा सेवाओं- विस्तार, प्रौद्योगिकी अंतरण, गुणवत्ता नियंत्रण आदि की उपलब्धता।

ये आजीविका संबंधी क्रियाकलाप समूह सदस्यों को उत्पादकता सुधार, बाजार जानकारी और विपणन सुविधा का लाभ तुरंत पहुंचाएंगे। ये औपचारिक क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित करके सदस्यों के उत्पादों की उचित कीमत दिलाने में भी उनकी मदद करेंगे।

भागीदारीपूर्ण आजीविका मैपिंग और विस्तृत आजीविका विश्लेषण तथा अंतरालों (मूल्य श्रृंखला में) के निर्धारण तथा पहल एवं सामूहिकीकरण के लिए अवसरों (बाजार से) के आधार पर, एसएचजी और परिसंघ परिसंघों में आजीविका संबंधी उप समितियों के जरिए पहल योजना बनाएंगे और कार्यान्वित करेंगे। उन्हें चलाने वाले और पर्याप्त लाभ उठाने वाले सदस्यों के पर्याप्त अनुभव मिलने के बाद, इन उप समितियों को अलग अलग आजीविका संगठनों- सहकारी समितिलों, उत्पादकों की कंपनियों आदि में परिवर्तित किया। जहां व्यवहार्य हो वहां इन संगठनों की प्रत्यक्ष रूप से मदद भी की जा सकती है।

कृषि आधारित मूल्य श्रृंखलाः एनआरएलएम मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा ताकि आजीविका समूह मूल्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण भाग पर विशेष ध्यान दे सके और बाजार के साथ संपर्क एवं जहां उचित हो वहां अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ साझेदारी करने का प्रयास कर सके। मूल्य श्रृंखला का विकास खाद्य, अनाज, डेयरी, ताजी सब्जियां आदि जैसे क्षेत्रों में मौजूद प्रमुख क्रियाकलापों और समूह के लिए महत्वपूर्ण विपणन अवसर के आसपास किया जाएगा। पारस्परिक रूप से लाभदायी इन साझेदारियों से देखी गई कीमतों में कमी आएगी और व्यावसायिक साझेदारों के लिए एकत्रीकरण के जोखिम एवं बाजार के उतार-चढ़ाव और निर्धनों एवं उनके समूहों के जोतों की लागत के जोखिम में कमी आएगी। इस बात को मानते हुए कि 75% से अधिक ग्रामीण निर्धन भूमि पर निर्भर हैं और पशुधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है, एनआरएलएम स्थायी कृषि के समूह क्रियाकलापों के विकास और डेयरी को एक सर्वव्यापी पहल के रूप में देखता है।

गैर कृषि समूहः एनआरएलएम स्थानीय संदर्भ और संसाधन की स्थिति के आधार पर, व्यापक सहायता के लिए गैर कृषि

उद्यमों के लिए कुछेक क्रियाकलापों/व्यापार समूहों का निर्धारण भी करेगा। समूह और सदस्य मूल्य श्रृंखला के बड़े हिस्से पर मिलकर काम करेंगे ताकि वे उपभोक्ता की राशि का महत्वपूर्ण अनुपात प्राप्त कर सकें। इस सहायता में कौशल विकास, डिजाइन/उत्पाद विकास, ऋण की उपलब्धता, कच्ची सामग्रियों की भारी मात्रा में खरीद, सामूहिक विपणन और मूल्य संवर्धन/ गुणवत्ता नियंत्रण/पैकेजिंग के लिए आम सुविधाओं की व्यवस्था एवं छोटे फर्मों के लिए आपूर्ति का ठेका शामिल होगा। इसे अधिमानतः गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी मोड में क्रियान्वित किया जाएगा।

इन कृषि और गैर कृषि समूहों के निर्माण तथा इससे संबंधित पहलों- मूल्य संवर्धन, बाजार अनुसंधान, बाजार जानकारी, विपणन सहायता, पूलिंग और विपणन आदि के लिए सहायता देने के लिए उपलब्ध आधारभूत एवं विपणन सहायता निधियों का उपयोग किया जाएगा।

एनआरएलएम प्रौद्योगिकी और जमीनी स्तर पर अभिनव पहलों को बढ़ाएगा तथा पूर्व परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा के बाद इनका प्रचार प्रसार करेगा। यह जमीनी स्तर पर गरीबों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुसंधान और तकनीकी संस्थाओं का नेटवर्क भी बनाएगा।

सार्वजनिक निजी सामुदायिक भागीदारीः एनआरएलएम निर्धनों के लिए आजीविका सहायता तथा वाणिज्य एवं बाजार संपर्क सेवा मुहैया कराने की दृष्टि से वैकल्पिक स्रोत तैयार करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के बीच सार्वजनिक निजी सामुदायिक भागीदारी बनाने का सक्रिय रूप से प्रयास करेगा। ये निर्धनों के लिए सह उत्पादन और आजीविका सहायता सेवाएं मुहैया कराने- कृषि विस्तारण सेवाएं; एग्री-इनपुट सप्लाई; प्रापण, ग्रेडिंग और कृषि व्यवसाय उपक्रमों के लिए प्रोसेसिंग फ्रेंचाइजीज; लॉजिस्टिक सुविधा प्रदाताओं, और जन सेवाओं, दूर-दराज में रहने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम और इससे संबंधित सेवाएं मुहैया कराने में काफी कारगर हैं।

लघु उत्पादकों के लिए स्थायी कृषि (एसएएसपी)

एनआरएलएम निर्धनों की समस्त भूमि को स्थायी कृषि के दायरे में देखता है। यह निर्धनों की जमीन पर खेती को बढ़ाने, खेती की लागत को कम करने, पारिवारिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ाने तथा उत्पादकता से समझौता किए बिना उनके लिए कृषि आय को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कम कीमत, कम जोखिम और अधिकतम श्रम बहुलता की वजह से अत्यंत निर्धनों में समुदाय प्रबंधित स्थायी कृषि की तरफ विशेष झुकाव है।

6-7 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किए जाने वाले इस कृषि प्रणाली दृष्टिकोण/प्रयास के प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- खेती की लागत को कम करना और स्थायी कृषि कार्यों को बढ़ावा देना जिनमें गैर कीटनाशक प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, फल उत्पादकता को बढ़ाने वाली कृषि (अर्थात् सिस्टम ऑफ राइस इंटेसीफिकेशन - एसआरआई) और पारिस्थितिकीय खेती शामिल हैं।
- प्रत्येक परिवार के लिए जैव विविधता योजना के लिए विविध फसलों और बहुस्तरीय मॉडलों का उपयोग करना।

- किसानों को संगठित करना, विभिन्न स्तरों पर एसएचजी परिसंघों में सीएमएसए उप समितियां बनाना तथा शेष सभी संबंधित स्टाफ को उनके प्रति जवाब देह बनाना।
- समुदाय में मौजूदा कमियों, सर्वश्रेष्ठ काम काम करने वालों और फार्मर्स फील्ड स्कूलों से समकक्ष शिक्षण समूहों के साथ विकेन्द्रीकृत विस्तारण प्रणाली।
- ग्राम स्तर, समूह स्तर और ब्लॉक स्तर पर समुदाय द्वारा भुगतान किए गए कार्यकर्ता/प्रेरक।
- विस्तारण और अन्य सेवाओं के लिए सदस्यों से शुल्क/अंशदान।
- स्व/समुदाय प्रबंधित नर्सरी, जैव-खाद और गैर-रासायनिक इनपुट/एजेंटों वाले दुकान।
- अनिवार्य अंग के रूप में पशुधन और पशुपालन।
- लीजिंग/अतिरिक्त सरकारी भूमि आदि उपलब्ध कराकर निर्धनों/अत्यंत निर्धनों के पास खेती योग्य जमीन को बढ़ाना।
- वर्षाजल एकत्रीकरण, प्रत्येक खेत में वृक्ष-आधारित फार्म बंद आदि सहित भूमि विकास और जल प्रबंधन/संरक्षण।
- महात्मागांधी नरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि मंत्रालय) के साथ तालमेल।
- प्रारंभ में एसएचजी परिसंघों में स्थानीय भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और एकत्रीकरण तथा महत्वपूर्ण क्रम के रूप में अलग से विशिष्ट संस्थान बनाए जाते हैं; बाजार संपर्क
- अंत में सम्पूर्ण प्रयासों का स्वामित्व एवं प्रबंधन करने के लिए उचित स्तर पर इसी दरम्यान स्थायी कृषि आधारित आजीविका समूह।
- सभी कृषकों का ई-डाटाबेस; स्थायी कृषि एवं बाजार आसूचना का पोर्टल; रीतियों, फसलों, उत्पादकता तथा कृषकों की आय की गणना
- एक विशेषज्ञ जिला संसाधन एजेंसी द्वारा प्रबंधित जिला संसाधन इकाई ।

इसके लिए निधियां अवसंरचना तथा विपणन सहायता कोष, तालमेल तथा सदस्यों के अंशदान से आहरित की जा सकती हैं । स्व सहायता समूह तथा परिसंघ व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आधार पर कार्यचालन पूंजी तथा परिसम्पत्तियों, यदि कोई हों, के अर्जन के लिए ऋण उपलब्ध करा सकते हैं ।

आजीविका के लिए अवसंरचना एवं विपणन कोष

आर्थिक क्रियाकलाप से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए एनआरएलएम में अवसंरचना तथा विपणन सहायता के लिए राज्य की वार्षिक एनआरएलएम योजना में कुल निधि परिव्यय के 20% तक (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) उपयोग का प्रावधान है । यह कोष एक सिरे से दूसरे सिरे तक गरीबों, उनके स्व सहायता समूहों, परिसंघों तथा आजीविका समूहों

के लिए आजीविका का समाधान उपलब्ध कराने के लिए है । यह कोष गरीबों के आजीविका क्रियाकलापों में मदद करने के लिए सॉफ्ट तथा हार्ड अवसंरचना के सृजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किंतु अवसंरचना के रख-रखाव पर होने वाले आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए नहीं । आगे, यह कोष विभिन्न लाइन विभागों के अवसंरचना निवेश के स्थानापन्न के लिए नहीं है । इस कोष से सृजित अवसंरचना स्व सहायता समूहों अथवा उनके परिसंघों अथवा गरीबों की आजीविका संगठन में निहित होगा ।

कुछ व्याख्यात्मक उद्देश्य, जिनके लिए इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है, निम्नानुसार है : -

i. प्रसंस्करण, भण्डारण तथा मूल्य संवर्धन के लिए उत्पादक अवसंरचना (एक बार)
ii. पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बाजार अनुसंधान इत्यादि के लिए विपणन सहयोग (एक बार)
iii. उत्पादकता वृद्धि तथा लागत / जोखिम न्यूनीकरण के लिए परामर्शी सेवाएं (एक बार)
iv. मेले तथा प्रदर्शनी आयोजित करना तथा मेले तथा प्रदर्शनी इत्यादि में स्व सहायता समूहों की भागीदारी

गरीबों के अथवा गरीबों के लिए संस्थान विभिन्न व्यवसाय भागीदारों - निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट भूमिका के साथ पूर्ण किंतु व्यवहार्य कार्य योजना को वास्तविकता देने के लिए इस कोष से निधियां ले सकते हैं । इस आकलन प्रक्रिया से आय में वृद्धि अथवा लागत / जोखिम में कमी अथवा कोई अन्य लाभ स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए । यह वित्त पोषण सहायता एक पूंजीगत अनुदान होगा । समुदाय आधारित अथवा सार्वजनिक बाजार सहयोग संगठन भी आपस में तथा गरीबों के संस्थानों के बीच स्पष्ट भागीदारी के आधार पर निधियों की मांग कर सकते हैं ।

अभिनव आजीविका परियोजनाएं

कुल एनआरएलएम केंद्रीय आवंटन का 5% आजीविका अभिनवता की सहायता करने के लिए अलग से रखा गया है । ये अभिनव परियोजनाएं राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं का भाग नहीं होतीं । उनका केंद्र स्तर पर अलग से आकलन तथा स्वीकृति की जाती है ।

अच्छी तरह से बनाई गई स्थायी आजीविका परियोजनाएं अपनी स्वयं की कार्यनीति, जिससे एक निश्चित संख्या में गरीब तथा कमजोर परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके, पर विचार किया जाएगा । इनमें आजीविका समूह संगठित करने, डिजाइन अथवा निर्माण में प्रशिक्षण देने, साझा अवसंरचना, प्रौद्योगिकी सहायता, विपणन इत्यादि शामिल हो सकते हैं ।

दिशानिर्देश सिद्धांत : अभिनव परियोजनाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं : -

- एक नई अवधारणा जिसने अवधारणा के स्थापित प्रमाण के साथ छोटे पैमाने पर अच्छा कार्य किया;
- उनकी मौजूदा आजीविका परिस्थिति की तुलना में गरीबों को पर्याप्त लाभ - अतिरिक्त रोजगार दिवस, उनके श्रम तथा सामान के लिए बेहतर कीमत के परिणाम, इनपुट तथा उत्पादन की न्यून लागत, ग्राम स्तर पर मूल्य संवर्धन इत्यादि;

- एक सिरे से दूसरे तक समाधान
- स्वयं गरीबों द्वारा प्रबंधित आजीविका संगठन
- बहु-राज्य परियोजनाएं अथवा एसआरएलएम के नेतृत्व वाली राज्य परियोजनाएं; तथा / अथवा
- भागीदारी आधारित (सार्वजनिक, निजी, समुदाय, भागीदारी (पीपीसीपी))- गरीबों की संस्थाएं, प्रौद्योगिकी प्रदाता, विपणन सेवा प्रदाता, वित्तीय समाधान प्रदाता इत्यादि

✓ गैर कृषि

✓ छोटे तथा सीमांत किसानों की पारिस्थितिकी तथा ऑर्गेनिक कृषि

✓ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय (आजीविका सुरक्षा); जनजातीय गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद संग्रहकर्ता (एनटीएफपी एकत्रण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन); समुद्र तटीय समुदाय (आजीविका सुरक्षा); पारिस्थितिकीय रूप से भंगुर अंचलों में आजीविका; आम जनता;

✓ कृषि एवं पशुधन में पर्याप्त मूल्य-संवर्धन तथा बाजार से संपर्क

✓ उन परियोजनाओं में अग्रणी बनाना जो वृद्धि उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है - उद्योग संघों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, निजी क्षेत्र, सरकार अथवा सिविल सोसाइटी संगठनों के सहयोग से; तथा / अथवा

✓ राज्य स्तर पर एसआरएलएम द्वारा अभिनवता, जो वे प्रयोग करना चाहेंगे ।

परियोजना की जांच तथा अनुमोदन : व्यापक परियोजना प्रस्तावों, जो अधिकतर मार्गदर्शन सिद्धांतों को पूरा करते हैं तथा दृष्टिकोण, कवरेज, संपर्क इत्यादि की अभिनवता तथा अद्वितीयता को स्पष्ट करते हैं, पर विचार किया जाएगा । ये परियोजना सहायता के लिए सीधे अथवा एसआरएलएम के माध्यम से एनआरएलएम / एनएमएमयू को प्रस्तुत की जा सकती हैं । प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की जांच पहले एनआरएलएम मिशन निदेशक की अध्यक्षता वाली परियोजना जांच समिति (पीएससी)[3] द्वारा की जाएगी। जांच की गई इस परियोजना को सिफारिशों के साथ सचिव, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) को उनके विचार तथा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

रोजगार संक्रांति

ये कार्यक्रम गहन तथा गैर-गहन ब्लॉकों, दोनों में शुरू किए जा सकते हैं ।

कौशल विकास तथा प्लेसमेंट

औपचारिक क्षेत्रों में प्रति गरीब परिवार एक रोजगार छोटी समयावधि में पूरे परिवार को गरीबी से बाहर लाता है । इससे स्थायी तथा उच्च स्तर की आय होती है । एनआरएलएम ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए कौशल की कमी को तथा शुरूआती बाधाओं को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ऊँची मजदूरी रोजगार की सुविधा देने के

[3] परियोजना जाँच तथा परियोजना अनुमोदन समिति के संघटन के लिए अनुबंध 2 देखें।

प्रयास करेगा । यह 'जॉब' समाधान को पूरा करने का प्रस्ताव रखेगा - बेरोजगारी की पहचान, कौशल प्रदान करना तथा उन्हें पुनः कौशल प्रदान करना, उन्हें रोजगार में नियोजित करना, सलाह देना तथा परामर्श देना, नया एक विद्यार्थी नेटवर्क को बढ़ावा देने वाला ।

ये कौशल विकास कार्यक्रम मांग जनित एवं नियोजन संबद्ध है। एनआरएलएम/एसआरएलएम जॉब संबद्ध पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले विशेषज्ञ संस्थाओं का एवं रोजगार अवसरों की खोज करने के लिए निजी सेक्टर के साथ नेटवर्क स्थापित करने का समर्थन करता है। ये कार्यक्रम गरीबों को बेहतर शर्तों, बेहतर कौशल, अधिकतम मजदूरी एवं विगत में आपदा के समय पलायन करने की जगह संवेदनशील सहायता नेटवर्क के साथ पलायन करने में सहायक होंगे।

विभिन्न कौशल विकास संघठनों के साथ सामान्यतः एवं निजी सेक्टर के साथ निश्चित रूप से भागीदारी का मॉडल बनाया जाएगा और आगे जारी रखा जाएगा। इसमें उद्योग समूह, सेक्टर निर्धारित कर्मचारियों का समूह, बैंक आदि भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मुख्य भागीदारों में से एक होगा। एनआरएलएम उद्योग एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के स्टेकहोल्डरों के साथ उच्च प्रोफाईल कौशल विकास परिषद को स्थापना की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीसी एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से भागीदारी करेगी जो सदस्यों के रूप में पूरे प्रयास को निर्देश देंगे। एनआरएलएम के केन्द्रीय आवंटन के 15 प्रतिशत को नियोजन-संबद्ध कौशल विकस के लिए निर्धारित किया गया है। आधे आवंटन (7.5 प्रतिशत) को एसआरएलएम वित्त पोषण पद्धति का पालन करते हुए (राज्यों को 75 : 25 या पूर्वोत्तर राज्यों को 90 : 10) दिया जाता है। कौशल विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समर्पित संस्थागत तंत्रों को बना लिया गया है एवं शेष को राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न राज्य कौशल विकास परियोजनाओं के लिए रखा जाता है।

इस घटक में एनआरएलएम/एसआरएलएम के वृहत कार्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

क. रोजगार/ नौकरी की आवश्यकता वाले ग्रामीण युवकों की पहचान।

ख. कस्टमाईज़ड जॉब समाधानों के लिए आपूर्ति शर्तों को बनाना एवं कार्यान्वित करना।

ग. नियोजन एजेंसियों एवं प्रत्यानन एजेंसियों की भागीदारी, प्रशिक्षण संस्थाओं, तकनीकी प्रशिक्षण एवं विकास संस्थाओं के साथ फ्रांचायजी व्यवस्था

घ. जॉब मार्केट में अत्यंत कम मांग व्यवस्था के निर्माण के लिए मांग में कौशल का निर्धारण, कर्मचारियों का सर्वेक्षण एवं कंपनियों को तैनात करना एवं एजेंसियों को भाड़े पर लेना।

ङ. सुरक्षित पलायन, चाइल्ड केयर, व्यावसायिक स्वास्थ्य सहायता एवं प्रेषण के लिए तंत्र सहित नियोजन एवं परिश्रमपूर्ण नियोजन के बाद सहायता सुनिश्चित करने के लिए सृजनात्मक तरीके।

च. वेब-आधारित ट्रेकिंग सिस्टम

बहु-राज्य परियोजनाओं की जांच एवं अनुमोदनः अधिकतम गरीबी से पिछड़े जिलों में निर्धारित फारमेट में बहु-राज्य कौशल विकास एवं नियोजन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव सीधे ऑन लाइन द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। परियोजना का आकार 15 करोड़ रु. के अंदर होना चाहिए। ये प्रस्ताव, जो परियोजना जांच समिति द्वारा जांच किए गए हैं, परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा जांच किए जाएंगे। पीएससी एवं पीएसी दोनों एक समान हैं क्योंकि ये दोनों अभिनव परियोजनाओं के लिए हैं। जांच, सिफारिश एवं अनुमोदन के प्रोटोकॉल भी समान हैं।

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

ग्रामीण विकास स्व रोजगार संस्थान द्वारा बनाया गया मॉडल पर आरएसईटीआई अवधारणा का निर्माण हुआ है- एसडीएमई ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक एवं केनरा बैंक के बीच सहयोगी भागीदारी। यह मॉडल व्यवस्थित दीर्घकालिक सहायता द्वारा अल्पकालिक अनुभवी शिक्षा प्राप्ति कार्यक्रम के जरिए बेरोजगार युवकों को आत्म-निर्भर उद्यमीकर्ता बनाने की संकल्पना करती है। आवश्यकता- आधारित प्रशिक्षण उद्यमिता की गुणवत्ता का निर्माण करता है, आत्मनिर्भरता की वृद्धि करती है, विफलता की जोखिम को कम करती है एवं प्रशिक्षुओं को परिवर्तनकारी एजेंट में बदलती है। बैंक अनुवर्तीय स्तरों पर चयन, प्रशिक्षण में पूरी तरह शामिल हैं। गरीबों की संस्थाएं सुस्पष्ट गरीबों की आवश्यकताओं आरएसईटी संस्थाओं को भागीदारों/ प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार एवं उद्यमों के उनके खोज में मार्गदर्शन करती हैं।

एनआरएलएम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में आरएसईटीआई संस्थाओं को आरंभ करने को प्रोत्साहन देता है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में एक आरएसईटीआई को आरंभ करने के लिए 1 करोड़ रु. का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा, राज्य सरकार जिलों में संस्थाओं के लिए उचित भूमि उपलब्ध कराएंगी। संस्थाओं की अन्य आवर्ती लागत प्रायोजक बैंकों द्वारा उठायी जाएगी। आरयूडीएसईटीआई बैंकों को एवं आरएसई संस्थाओं को अपने कार्यक्रमों की क्षमता में वृद्धि लाने के लिए व्यवस्थित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। आरएसईटी संस्थाओं को तकनीकी सहायता के क्षेत्रों में प्रशिक्षु चयन प्रणाली, विषय में विकास, ट्रेनिंग पेडागोगी, एमआईएस एवं प्रशिक्षण के पश्चात् अनुवर्ती तंत्र भी शामिल हैं। आरएसईटी संस्थाओं के स्नातकों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात् अनुवर्ती तंत्र में इंटरेक्टिव वेब पोर्टल, कॉल सेंटर, बिजनेस काउंसिलिंग सेंटर एवं अल्युमिनी कन्वेंक्शन का नेटवर्क शामिल है। इसके अतिरिक्त, उसके अधिदेश एवं एजेंडा पूरा करने के लिए अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। आरएसईटीआई की परिचालन नियमावली आरएसईटी संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगी।

अध्याय - 4
तालमेल एवं साझेदारी

<u>तालमेलः-</u>

भारत सरकार और राज्य सरकार गरीबी एवं उपेक्षा के विभिन्न आयामों को हल करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। गरीबों को प्रभावित करने वाले प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों को निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

- हकदारी- जन वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा, सूचना का अधिकार आदि।
- जीवन स्तर में सुधार करना- स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्थायी आवास, बिजली आदि।
- क्षमता संबर्द्धन करना- प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा, कौशल संबर्द्धन आदि।
- आजीविका का अवसर पैदा करना- संस्थागत वित्त, कृषि, पशुपालन, वाटरशेड, एमएसएमई विकास, खाद्य प्रसंस्करण आदि।
- भौतिक अवसंरचना योजना- सड़क, विद्युत, दूरसंचार आदि।

ये असमावेशी नहीं हैं और विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत कई श्रेणियां कवर हो सकती हैं।

गरीबों की संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित लाइन मंत्रालयों के बीच संपर्क कर इन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में बहुत वृद्धि की जा सकती है। इन साझेदारी से उन्हें सेवा सुपुर्दगी के लिए विभिन्न मॉडल बनाने और गरीबों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सकता है। एनआरएलएम/एसआरएलएम ये साझेदारी विकसित करने और सहयोग बढ़ाने संबंधी कार्य करेगा।

उदाहरणार्थ, एमजीएनआरईजीएस एवं एनआरएलएम सहयोग स्थापित कर उनकी प्रभावकारिता और प्रभाव में सुधार करने के लिए तालमेल की संभावना प्रस्तुत करता है। एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार एवं प्राकृतिक संसाधनों का विकास और सामुदायिक एवं आजीविका संबंधी परिसंपत्तियों के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। एनआरएलएम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीब संगठित कर लिए गए हैं। यदि मिला दिया जाए तो एनआरएलएम से उनकी नियमित बैठकों में एमजीएनआरईजीएस पर चर्चा करने के लिए ग्राम स्तर पर गरीबों की संस्था को सुविधा मिलेगी। इसे जॉब कार्ड बनाने, कार्यों का चयन, मजदूरी भुगतान में सहायता करने, एमजीएनआरईजीएस में हकदारी और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि कार्य में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनआरएलएम के अंतर्गत उन गरीबों को सहबद्ध किया जाएगा जिनकी जमीन एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत तकनीकी जानकारी, कौशल उन्नयन, बैंक ऋण एवं विपणन से विकसित की गई है।

इसी तरह, एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, समेकित वाटरशेड प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान और अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल पर जोर दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को अपना उचित लाभ मिल रहा है। इससे उनके द्वारा आजीविका के सृजित अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी।

पंचायती राज, मानव संसाधन विकास, कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वस्त्र, एमएसएमई (केवीके) महिला एवं बाल विकास, वित्तीय सेवा, पर्यटन इत्यादि मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ तालमेल के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, एनआरएलएम के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ विभागों द्वारा गरीबों को संगठित किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा तथा इस पर कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि जैसे कार्यक्रमों के साथ तालमेल के जरिए जीवन, परिसंपत्तियों और स्वास्थ्य के नुकसान की स्थिति में ग्रामीण गरीबों के सर्वव्यापी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पहल की जाएगी।

साझेदारी

एनआरएलएम अपने महत्वाकांक्षी कार्यों के प्रति सजग रहते हुए विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ कार्य, हिस्सेदारी और साझेदारी करेगा। ये स्टेक होल्डर शिक्षण, विशेषज्ञता, लागत एवं संसाधनों में हिस्सेदारी करेगा, विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन, सक्रिय सहायक भूमिका और कार्य शुरू करेगा, प्रायोगिक कार्य संचालित करेगा, मॉडल प्रदर्शित करेगा, प्रशिक्षण देगा और क्षमता निर्माण करेगा, संसाधन समूह और केन्द्र बनाएगा, संपर्क उपलब्ध कराएगा, ज्ञान का सृजन, प्रबंधन और इसका प्रचार-प्रसार करेगा, सहयोग करेगा।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य सिविल सोसाइटी संगठन (सीएसओ)

निचले स्तर के समृद्ध अनुभव और गैर सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रदर्शन से मिली सीख ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य के विभागों को प्रभावित किया है ताकि आजीविका में सुधार करने और गरीबी दूर करने के लिए नई कार्यनीतियां बनाई जा सके तथा मौजूदा कार्यनीतियों में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। एनआरएलएम के मुख्य मतों एवं मूल्यों द्वारा निर्देशित, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साझेदारी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में उनके साथ साझेदारी महवपूर्ण होगी।

एनआरएलएम के अंतर्गत प्रक्रियाओं एवं परिणामों पर आपसी करार के अध्यधीन दो स्तरों- कार्यनीतिगत एवं कार्यान्वयन स्तर पर विभिन्न भौगोलिक एवं विषयगत क्षेत्रों में साझेदारी की जाएगी। आयोजना साझेदारी के लिए यह गैर-सरकारी संगठनों/ सिविल सोसाइटी संगठनों और उनके सामाजिक जुटाव तथा विषयगत प्रयासों की मौजूदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

साझेदारी के कुछ संभाव्य क्षेत्रों में शामिल होंगेः

i. गांवों और ब्लॉकों के विशिष्ट समूह में कार्यक्रम का कार्यान्वयन

ii. महत्वपूर्ण मौजूदगी के क्षेत्रों में विषयगत सहयोग का समग्र विस्तार करना

iii. उनकी क्षमता के मुख्य क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध कराना

iv. लाइन मंत्रालयों की विभिन्न पहलों के साथ स्वसहायता समूहों उनके परिसंघों को आबद्ध करना

v. अभिनव कार्य

vi. संयुक्त नीतिगत समर्थन और शिक्षण मंच/स्थल; और

vii. एनआरएलएम के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ सतत् वार्ता।

अन्य स्टेकहोल्डरों में निजी क्षेत्र, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व इकाई, फिलेनथ्रोपिक फाउण्डेशन/ट्रस्ट, प्रशिक्षण संस्थान/ केन्द्र आदि शामिल हैं। उद्योग संघ आवधिक एचआर एवं कौशल मूल्यांकन तथा बाजार अध्ययन के साथ कौशल विकास एवं नियोजन के लिए कार्यनीति बनाने की जानकारी देगा। वे पाठ्यक्रम की रूपरेखा, गुणवत्ता आश्वासन एवं परामर्श, आदि सहित रोजगार मूल्य श्रृंखला के मांग पक्ष पर जोर देगा।

शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाएं: एनआरएलएम विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक रूप से सक्षम एवं समर्पित कार्यान्वयन संरचना पर जोर देते हुए पाठ्यक्रम की रूपरेखा, प्रशिक्षण शिक्षा शास्त्र, संकाय/ प्रशिक्षक विकास और प्रशिक्षण तथा पेशागत विकास के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ साझेदारी करेगा। यह रुझानों की निगरानी करने के लिए क्षेत्र/कार्य अनुसंधान, सामाजिक प्रेक्षणशाला के जरिए अनुसंधान/समीक्षात्मक साधन और नीति एवं कार्यनीतिगत आयोजना के लिए अनुसंधान संस्थाओं/उत्कृष्ट केन्द्रों के साथ साझेदारी करेगा।

सार्वजनिक-सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी, सार्वजनिक-निजी सामुदायिक भागीदारी: एनआरएलएम, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों के साथ कार्य करेगा। इससे चुनिंदा मूल्य श्रृंखला अथवा उत्पाद समूह बनाने के लिए आजीविका के मुख्य क्षेत्रों यथा- कृषि, पशुधन, गैर-कृषि क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी के लिए मंच तैयार होगा। इससे मूल्य श्रृंखला आधारित कार्य साझेदारी और विपणन संपर्क कायम होगा। इससे गरीबों के लिए विविध भागीदारी भी कायम होगी ताकि वे अपने अधिकारों तथा हकदारी, जन सेवाएं, विशेषज्ञता और अन्य सेवाओं का और अधिक लाभ उठा सकें।

अध्याय - 5
पंचायती राज संस्था

पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय आर्थिक विकास, गरीबी उपशमन और सामाजिक न्याय में संवैधानिक भूमिका है। पंचायतों और गरीबों की संस्थाओं के बीच परस्पर लाभदायी कार्यकारी संबंध बनाने तथा परामर्श के लिए औपचारिक मंच उपलब्ध कराने के लिए लोकतंत्र को सुदृढ़ करने तथा गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने की आवश्यकता है। गरीबों की संस्थाओं की स्वायत्ता को परिरक्षित/ संरक्षित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। परस्पर सलाह, सहयोग और पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों की हिस्सेदारी के लिए नियमित परामर्श किए जाने की आवश्यकता है। जहां पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व/मान्यता प्राप्त नहीं हैं पारंपरिक स्थानीय ग्राम संस्थाएं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका निभाएंगीं।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाः पंचायती राज संस्थाओं को एनआरएलएम के विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। उनकी सहभागिता/भागीदारी के संकेतात्मक क्रियाकलाप में शामिल होंगेः

(i) अत्यंत निर्धन और उनमें सर्वाधिक दुर्बल व्यक्तियों के लिए आरंभिक प्राथमिकता के साथ बीपीएल परिवारों को निर्धारित करना और स्वसहायता समूहों में संगठित करना;

(ii) विभिन्न स्तरों पर एसएचजी परिसंघों को सुविधागत बनाना और उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना

(iii) पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक योजनाओं/क्रियाकलापों के स्वसहायता समूहों और उनके परिसंघों की प्राथमिक मांगों को शामिल करना और उनके लिए उपयुक्त वित्तीय आवंटन करना, और

(iv) एसएचजी नेटवर्क की ओर से विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

गरीबों की संस्थाओं की जिम्मेदारियां: इसके बाद गरीबों की संस्था निम्नलिखित जिम्मेदारियां वहन कर सकती हैं :

(i) ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भागीदारी करना;

(ii) समुदाय आधारित निगरानी के जरिए फीडबैक उपलब्ध कराना;

(iii) पंचायती राज संस्थाओं की विकासात्मक पहलों को सहयोग देना; और

(iv) पंचायती राज संस्थाओं को अपने आयोजना संबंधी कार्यों में सहयोग देना।

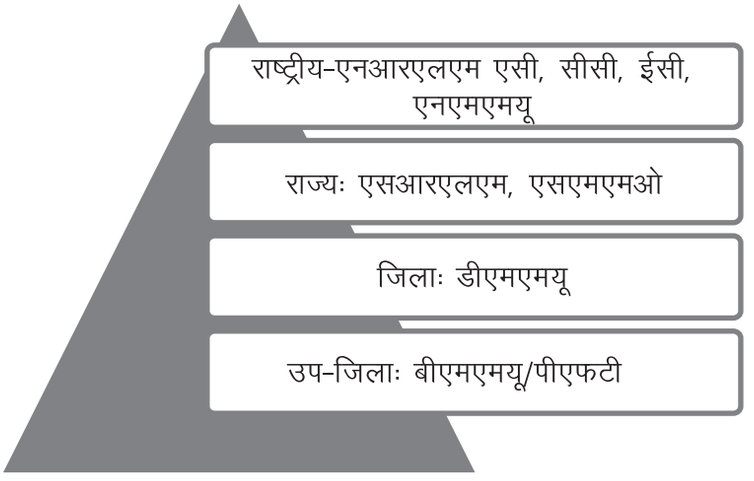
ऐसी स्थिति में जहां पंचायती राज संस्थाओं और गरीबों की संस्थाओं के बीच संबंध सुदृढ़ हो गया है, पंचायती राज संस्थाएं उन्हें पंचायत के संसाधन (यथा- मत्स्य तालाब, सार्वजनिक सम्पत्ति, बाजार परिसर आदि) पट्टे पर दे सकती हैं और चुनिंदा नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने, नागरिक कार्यों को कार्यान्वित करने, सेवा सुपुर्दगी के विस्तार एवं निष्पादन तंत्र के लिए उन्हें जिम्मेदारियां सौंप सकती है।

ये संपर्क/सहयोग महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को गरीबी, सामाजिक न्याय एवं एनआरएलएम की अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। गरीबों की संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और उनके साथ सघन समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता के संबंध में जागरूक बनाया जाना चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श के लिए तंत्रः गरीबों की संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं के बीच नियमित विचार-विमर्श के लिए औपचारिक तंत्र महत्वपूर्ण है। एनआरएलएम साथ-साथ कार्य करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और एसएचजी नेटवर्क, जानकारी और विचार का आदान प्रदान करने, संसाधन जुटाने एवं आयोजना तथा नियमित निगरानी के लिए मंच उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, यह आजीविका संबंधी परिणामों के लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रति वर्ष पंचायती राज संस्थाओं/ गांवों का निर्धारण, मूल्यांकन करेगा और उन्हें पुरस्कृत करेगा। इसके लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एवं उत्साहवर्द्धक फ्रेमवर्क विकसित एवं कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्याय - 6
सहायक संरचना

एनआरएलएम सामाजिक जुटाव तेज करने, संस्थाएं बनाने, क्षमता एवं कौशल निर्माण करने, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुविधागत बनाने, आजीविका और विभिन्न कार्यक्रमों, स्टेक होल्डरों के साथ तालमेल एवं साझेदारी का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, एवं उप-जिला स्तरों पर समर्पित सक्रिय सहायक इकाई स्थापित करेगा। इन इकाइयों में व्यावसायिक रूप से सक्षम एवं समर्पित मानव संसाधनों की तैनाती की जाएगी।



राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना

राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एनआरएलएम संबंधी सलाहकारी समिति[5] है। इनमें सिविल सोसाइटी संगठनों, वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात उद्योग संघ एवं शिक्षाविद, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। नीति निर्माता निकाय के रूप में एनआरएलएम के समग्र दृष्टिकोण, निदेशन एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा और समग्र प्रगति की समीक्षा करेगा।

सचिव, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एनआरएलएम समन्वयन समिति (एनआरएलएम-सीसी) एनआरएलएम की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उद्देश्य समय पर पूरे कर लिए गए हैं। एनआरएलएम संबंधी अधिकार संपन्न समिति (एनआरएलएम-ईसी) राज्य सदर्शी एवं कार्यान्वयन योजना तथा वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा एवं अनुमोदन करेगी और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को निधियां रिलीज करेंगी।

संयुक्त सचिव/अपर सचिव, एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिशन निदेशक एवं राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन एकक जिसमें संविदा पर खुले रूप से पेशेवरों का बहुविषयक दल तथा पर्याप्त सहायक स्टाफ रहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में एनआरएलएम का नेतृत्व करता है। सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन और आजीविका में विषयगत उप समूह

[5]एनआरएलएम सलाह, समन्वय और अधिकार संपन्न समितियों के संघटन के लिए अनुबंध 2 देखें

स्थापित किए जाएंगे। एनएमएमयू के भीतर तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ (टीएससी) राज्यों को तकनीकी सहायता और बहुविषयक मूल्यांकन मिशनों का समन्वय करेगा। टीएससी राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों, एनएमएमयू, राज्य मिशनों और विकास क्षेत्र से लिए गए सभी संबंधित विषयों के सलाहकारों और विशेषज्ञों का समूह बनाएगा और उसका संचालन करेगा। एनएमएमयू में विशेष प्रकोष्ठ नियोजन संबद्ध कौशल विकास और अभिनव आजीविका परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार होंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता

एनआरएलएम सभी स्तरों पर और सभी साझेदारों बैंकों, सार्वजनिक एवं निजी-क्षेत्र तथा गरीबों की संस्था में क्षमता सृजित करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।

ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माणः राष्ट्रीय स्टेक होल्डरों की कार्यशाला, परामर्श और नीति संबंधी गोष्ठी के अतिरिक्त, एनआरएलएम के अंतर्गत आजीविका में जानकारी, अनुभव एवं अभिनव ज्ञानों के आदान-प्रदान के लिए बहु-स्टेकहोल्डर मंच, आईसीटी आधारित शिक्षण एवं वेब समर्थित ज्ञान प्रबंधन प्रणाली/मंच को सहयोग दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं :

(क) एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक राज्यों में समुदाय संसाधन व्यक्ति उपलब्ध कराने और तकनीकी सहायता देने के लिए समुदाय संसाधन केन्द्र (उत्कृष्ट केन्द्र) बनाना।

(ख) सामाजिक जुटाव और आजीविका संवर्द्ध में राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकारी और/अथवा सिविल सोसाइटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कार्यान्वयन में अनुभव से क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय संसाधन संगठन को सुदृढ़ करना।

(ग) विकास पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाना और शिक्षाविद, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ सहयोग के जरिए उनका क्षमता निर्माण करना।

बैंक एवं बाजार संपर्क के लिए साझेदारी विकसित करनाः एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब के लिए वित्तीय उपलब्धता सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ राज्यों के जरिए कार्यनीतिगत साझेदारी को सुविधागत बनाया जाएगा। इससे उत्पादन क्षमता बढने, अवसंरचना एवं सूचना सेवा सृजित करने एवं गरीबों के अनुकूल बाजार तंत्र बनाने में सहायता करने के लिए सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी को भी सुविधागत बनाया जाएगा।

एनआरएलएम के संचालन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देनाः एनएमएमयू निर्धनता निर्धारण, राज्य संदर्श योजना तथा वार्षिक योजनाएं बनाने और प्रायोगिक कार्य संचालन मे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। यह विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायक संरचना और वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण जैसी कार्यक्रम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में सहायता देगी। यह विभिन्न स्तरों पर पेशेवरों का दल तैनात करने (एनएमएमयू इस प्रयोजनार्थ विख्यात एचआर एजेंसियों का पैनल रखेगा) तथा उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगा।

राज्य स्तर पर सहायक संरचना

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम): राज्य सरकार द्वारा गठित एसआरएलएम राज्य में एनआरएलएम से

संबंधित सभी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की जांच करेगा। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में एसआरएलएम को सोसाइटी, न्यास अथवा कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा। शासकीय निकाय (जीबी) और कार्यकारी समिति (ईसी)[6] आयोजना एवं कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन एवं सलाह देगी। विशेषकर मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव शासी निकाय की अध्यक्षता करेंगे और प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास इसके सदस्य सचिव/संयोजक होंगे। विशेषकर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त कार्यकारी समिति की अध्यक्षता करेंगे और प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास इसके उपाध्यक्ष एवं राज्य मिशन निदेशक इसके संयोजक होंगे।

राज्यों में जहां राज्य सरकारें एसआरएलएम के रूप में मौजूदा सोसाइटी का उपयोग करना चाहेंगी, इसके संगम ज्ञापन/उपनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि एनआरएलएम के उद्देश्यों को शामिल किया जा सके और उपर्युक्त की तर्ज पर शासी निकाय में सदस्यता का विस्तार किया जा सके।

राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एसएमएमयू) : एसआरएलएम पूर्वकालिक राज्य मिशन निदेशक (एसएमडी) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय एसएमएमयू के जरिए राज्य में एनआरएलएम क्रियाकलापों का निष्पादन करेगी। एसएमडी का कार्यकाल अधिमानतः तीन वर्ष होगा। एसएमडी वे वरिष्ट अधिकारी होंगे जिन्होंने विशेषकर जिला कलक्टर के रूप में पहले ही कार्य कर लिया हो।

एसएमएमयू की प्रमुख जिम्मेदारियां होंगीः

- राज्य में एनआरएलएम के सभी क्रियाकलापों का नेतृत्व करना;
- राज्य स्तर पर मिशन की नीतियों एवं कार्यक्रम दिशा-निदेर्शों का प्रारूप तैयार करना;
- जिला एवं उप-जिला कार्यान्वयन/सहायक संरचनाओं को मौके पर सहायता देना;
- विभिन्न घटकों/विषयगत सहयोगों का गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ समुचित संपर्क सुनिश्चित करना;
- तालमेल एवं साझेदारी को प्रबंधित करना;
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य कार्य।

एसएमडी के अतिरिक्त, बहुविषयक एसएमएमयू दल में सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, आजीविका, कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यक्रम संबंधी सहायता में विशेषज्ञ आदि और सहायक स्टाफ शामिल होंगे। संबंधित विषयगत क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले ये विशेषज्ञ बाहर से अथवा संविदात्मक आधार पर अथवा विशिष्ट विचारार्थ विषय के साथ प्रतिनियुक्ति आधार पर सरकारी संगठनों से लिए जाएंगे। उनका नियोजन आवश्यकतानुसार चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। सहायक स्टाफ ठेका पर होगा। आवश्यकता के आधार पर, सहायक (वरिष्ठ परिचालन अधिकारी) के रूप में वरिष्ठ विकास कर्मी बाहर से लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसएमएमयू क्षेत्रीय कार्यान्वयन दल की सहायता करने के लिए विषयगत विशेषज्ञ अथवा सूचीबद्ध विख्यात संसाधन एजेंसियों को कार्य में लगाएंगीं।

[6]एसआरएलएम शासी निकाय और कार्यकारी समिति के संकेतात्मक संघटन के लिए अनुबंध 3 देखें

आजीविका कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली विविध एजेंसियों वाले राज्यः कुछ राज्यों में एनआरएलएम के उद्देश्यों से संबद्ध क्रियाकलापों में विविध एजेंसियां/विभाग शामिल हैं। इनमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं अथवा महिला एवं बालविकास, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण आदि विभागों के कार्यक्रम शामिल हैं। एनआरएलएम ऐसी सभी पहलों के कवर करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। तालमेल के मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल हैं : मौजूदा साझेदारों की संख्या का लाभ उठाया जाता है, मौजूदा सामाजिक एवं मानवीय पूंजी का नुकसान नहीं होता है, एनआरएलएम के अपर क्राम्य सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है और प्रयास की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। एसआरएलएम उपयुक्त सरकारी संगठन के साथ साझेदारी करेगा और उन्हें कार्यान्वयन संबंधी जिम्मेदारियां सौंपेगा।

जिला स्तर पर सहायक संरचना

जिला मिशन प्रबंधन इकाई (डीएमएमयू): एसआरएलएम का डीएमएमयू एनआरएलएम के उद्देश्यों को पूरा करने और जिले में एनआरएलएम के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगी। डीआरडीए से सुसंबद्ध डीएमएमयू क्षेत्र संरचनाओं के लिए सुविधा प्रदाता एवं सहायक इकाई होगी। यह जिला प्रशासन; लाइन विभागों, बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों और निगमित एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करेगा और तालमेल स्थापित करेगा। जिला कलक्टर की अध्यक्षतावाली व्यापक जिला सलाहकारी समूह/समीक्षा और समन्वय समिति जिसमें गरीबों की संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं गैर-सरकारी संगठन जो उनके साथ सही तरीके से कार्य करते हैं, शामिल हैं, एनआरएलएम के क्रियाकलापों की समीक्षा करेगी और अनुवर्ती योजनाओं में सुधार एवं विकसित करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगी।

ठेका पर खुले बाजार से अथवा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए जिला मिशन प्रबंधक (डीएमएम) की अध्यक्षतावाली बहुविषयक डीएमएमयू में सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, आजीविका, क्षमता निर्माण, कार्यक्रम प्रबंधन कार्यक्रम सहायता आदि में कार्यकारी विशेषज्ञ और आवश्यकतानुसार सहायक स्टाफ शामिल है। इन विशेषज्ञों और स्टाफ को आवश्यकतानुसार ठेका पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर चरणबद्ध से कार्य में लगाया जाएगा।

डीएमएमयू के भीतर क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ क्षेत्र कार्यान्वयन इकाइयों को प्रशिक्षण देने और गरीबों में से समुदाय संसाधन व्यक्तियों का संपोषण करने और उन्हें प्रशिक्षकों के रूप में विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रारंभ में डीएमएमयू स्टाफ स्वयं प्रशिक्षक हो सकते हैं। जैसे-जैसे कार्यक्रम का विस्तार होगा, क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ बाहरी संसाधन व्यक्तियों को सूचीबद्ध करेगा।

<u>उपजिला स्तर पर सहायक संरचनाः</u>

उपजिला स्तरीय सहायक संरचना है -

- ब्लॉक मिशन प्रबंधक (बीएमएम) की अध्यक्षतावाली ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई और 3-5 व्यक्तियों का एक दल, अथवा
- समूह (उप-ब्लॉक) स्तर पर परियोजना सुविधा प्रदाता दल
- दोनों का सम्मिलित रूप।

ब्लॉक मिशन प्रबंधकों सहित उप-जिला संरचना के सदस्य खुले बाजार से अथवा प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाएंगे।

इन उप-जिला क्षेत्र दल/संरचना की प्रमुख जिम्म्दारियों में शामिल हैं : सभी ग्रामीण परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित करना, मौजूदा एवं नये स्वसहायता समूहों को सुदृढ़ बनाना, विभिन्न स्तरों पर एसएचजी परिसंघ तथा गरीबों की अन्य संस्थाएं बनाना, गरीबों तथा उनकी संस्थाओं, सीआरपी और अन्य सामाजिक पूंजी का क्षमता निर्माण। ये संस्थाएं 2-3 वर्ष की अवधि में सभी सहयोग जारी रखने की जिम्मेदारी वहन करेगी। ये उप-जिला दल इसके लिए समर्पित रहेंगे और पुनः प्रशिक्षण के साथ उभरने वाली नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। ये उप-जिला इकाइयां गैर-सरकारी संगठनों अथवा सिविल सोसाइटी संगठनों अथवा सरकारी संगठनों द्वारा ब्लॉक में पहले से हासिल किए गए सामाजिक जुटाव और संस्था निर्माण को ध्यान में रखेंगी। ब्लॉक के लिए कार्य योजना जमीनी स्थिति के क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित होगी। कार्य योजना जमीनी कार्य को सुदृढ़ करेगी और कवर न किए गए क्षेत्रों को कवर करने के लिए योजना बनाएगी।

ये दल ब्लॉक प्रशासन और गरीबों की संस्थाओं के बीच सक्रिय सहयोग के लिए तंत्र को बढ़ावा देंगे। जैसे-जैसे क्षमता धीरे-धीरे बढ़ती है गरीबों की संस्थाएं- स्वसहायता परिसंघ स्वयं ब्लॉक प्रशासन के साथ विचार-विमर्श तथा तालमेल स्थापित करते हैं। ब्लॉक समीक्षा और समन्वय समिति जिनमें गरीबों की संस्थाओं के प्रतिनिधि और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं और जो उनके साथ उल्लेखनीय रूप से कार्य करते हैं, ब्लॉक में एनआरएलएम क्रियाकलापों की समीक्षा करेंगे और अनुवर्ती योजनाओं में सुधार करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

मानव संसाधन (एचआर) संबंधी नीति और प्रशासनिक एवं वित्त नियम

मानव संसाधन संबंधी नीतिः एनआरएलएम का मानना है कि उसकी सफलता विभिन्न स्तरों पर समर्पित सजग सहायक संरचना की एवं उनके स्टाफ की गुणवत्ता एवं व्यावसायिक दक्षता से संबद्ध है। विभिन्न स्तरों पर मौजूदा स्टाफ पैटर्न भू स्थिति, ब्लॉकों की संख्या, जनसंख्या विस्तार, कार्यान्वयन कार्यनीति एवं चरणबद्ध प्रक्रिया पर आधारित होगा। प्रत्येक राज्य तदनुसार योजना बनाएंगे/ समायोजन करेंगे और उनकी अपनी मानव संसाधन संबंधी नीति और नियमावली होगी जिसमें आवधिक रूप से संशोधन किया जाएगा। मानव संसाधन संबंधी नीति में मुख्य अवयवों में स्टाफ, कार्य की रूपरेखा/दक्षता, भर्ती एवं चयन, पादर्शिता, प्रवाह एवं आगमन, पारिश्रमिक, निष्पादन प्रबंधन, मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन, शिकायत निवारण, स्टाफ शिक्षण और क्षमता निर्माण, विभिन्न फार्मेट में मानव संसाधन के लिए स्थान एवं कार्यकाल- पूर्णकालिक, अंशकालिक, गृह आधारित, अल्पकालीन/दीर्घकालीन स्थानबद्धता, सप्रभवर्षीय (सब्बाटिकल) एवं तैनाती संबंधी छूट शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन नीति के अंतर्गत सहायक संरचनाओं में स्टाफ के रूप में सामुदायिक पेशेवरों/सीआरपी को उनकी औपचारिक योग्यताओं का संदर्भ लिए बिना शामिल करने, सहायक संरचनाओं एवं स्टाफ की बदलती भूमिका और गरीबों की संस्थाओं में कुछ स्टाफ को सहयोग करने पर चर्चा की जाएगी।

मानव संसाधन आवश्यकता की आयोजना करते समय गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साझेदारी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्टाफ शिक्षण एवं क्षमता निर्माणः एनआरएलएम के अंतर्गत स्टाफ शिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए समर्पित एवं पर्याप्त

बजट आवंटन किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ कार्यान्वयन के दौरान मिशन शिक्षण को समेकित करने के लिए सभी स्तरों पर व्यवस्थित प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमः स्वतंत्र कार्यान्वयन एजेंसियां होने के कारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियम बनाए एवं कार्यान्वित किए जाएंगे जो समुदाय की आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने एवं कुशल पेशेवर स्टाफ की संपोषण एवं संचालन के लिए शिथिलता के साथ प्रक्रिया बहुल एनआरएलएम के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधागत बनाता है।

अध्याय - 7
निगरानी, मूल्यांकन एवं शिक्षण

एनआरएलएम बहुल प्रक्रिया है और इसीलिए इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर हासिल गुणात्मक एवं परिणात्मक प्रगति की सतत् समीक्षा, मूल्यांकन एवं शिक्षण किया जाएगा। शिक्षण एवं सतत् सुधार को सुविधागत बनाने एवं सभी स्तरों पर सजग निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता देने के लिए सुदृढ़ आई टी आधारित निगरानी, मूल्यांकन एवं शिक्षण प्रणाली स्थापित की जाएगी।

निगरानी तंत्रः एनआरएलएम के अंतर्गत निगरानी के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए जाएंगेः

(i) गरीबों की संस्थाओं के दायित्व में संस्थागत स्वतः निगरानी, प्रक्रियाओं एवं स्थानीय सामाजिक लेखा परीक्षा की मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा शामिल है।

(ii) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) इनपुट-आऊटपुट मॉनिटरिंग पर आधारित है, इसमें परिणाम फ्रेमवर्क आधारित एमआईएस इनवेस्टमेंट/इनुपट से संबद्धित उपलब्धि, वेब आधारित एमआईएस, विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध इनपुट आऊटपुट मॉनिटरिंग और साझेदारों के आंकड़ों के साथ एमआईएस शामिल हैं।

(iii) डेडीकेटेड डिजिटल ग्रिड के लिए आईसीटी फ्रेमवर्क में गरीबों का राष्ट्रीय डाटाबेस, उनकी संस्थाओं और कौशल विकास (रोजगार/स्वरोजगार), राष्ट्रीय आजीविका पोर्टल, संचार/ज्ञान प्रसार चैनल, विषयगत ई-समूह आदि शामिल हैं।

(iv) विभिन्न स्तरों पर आंतरिक समीक्षा तंत्र-

- मासिक/तिमाही आयोजना/प्रगति/प्रक्रिया की रिपोर्ट देना एवं आंतरिक समीक्षा
- स्टाफ/अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरा, एसआरएलएम से जिला एवं क्षेत्र तक पर्यवेक्षण का आवधिक दौरा और समय-समय पर विषय विशिष्ट पर्यवेक्षण दौरा
- राज्यों के लिए संयुक्त अर्द्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा, आयोजना/ पर्यवेक्षण मिशन
- स्वतंत्र प्रक्रिया निगरानी
- विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ समीक्षा एवं परामर्श कार्यशाला; और
- विभिन्न स्तरों पर कार्यकारी समितियों, शासी निकायों, सलाहकारी समूहों/समितियों, तालमेल संबंधी मंच, समन्वयन समितियों की बैठकें।

(v) बाह्य सामाजिक लेखा परीक्षा, लोक व्यय अन्वेषण एवं समुदाय स्कोरकार्ड।

(vi) प्रभाव मूल्यांकन - मुख्य परिणाम संकेतकों के संबंध में प्रगति का राज्य स्तरीय बेसलाइन मूल्यांकन और

बाह्य अंतरिम प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आवधिक अंतरालों पर पैनल अध्ययन के जरिए परिवार कल्याण का स्वतंत्र राष्ट्रीय मूल्यांकन, नमूना जिला स्तरों पर परिणामात्मक मूल्यांकन और आवधिक विषयगत राष्ट्रीय मूल्यांकन को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

(vii) एसआरएलएम वार्षिक रिपोर्ट और एनआरएलएम वार्षिक रिपोर्ट।

ज्ञान प्रबंधन, शिक्षण एवं समर्थनः उपर्युक्त निगरानी तंत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पोर्टल, विभिन्न स्तरों पर ई-संचार और शिक्षण समूह, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय श्रव्य-दृश्य, रेडियो एवं दूरदर्शन आधारित संचार माध्यम/नेटवर्क आदि एनआरएलएम में शिक्षण, सुलभ बनाने और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण तरीके होंगे। जन प्रतिनिधियों एवं पंचायती राज संस्थाओं को कार्य में लगाने, उनकी आजीविका संवर्द्धन करने और आजीविका कार्यसूची बनाने के अतिरिक्त एनआरएलएम के अंतर्गत उन्हें उनके क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र में एनआरएलएम की प्रगति की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एनआरएलएम के अंतर्गत देश में आजीविका संबंधी नीतिगत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय - 8
वित्तीय प्रबंधन

राज्यों को निधियों का आवंटन

एनआरएलएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के अलावा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है । मिशन के वित्तपोषण को निम्नलिखित आधार पर केंद्र तथा राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वहन किया जाएगा :

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय अंश (%)	राज्य अंश (%)
1.	पूर्वोत्तर राज्य (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम)	90	10
2.	अन्य सभी राज्य	75	25
3.	संघ राज्य क्षेत्र	100	0

एनआरएलएम के लिए कुल आवंटन में से 20% कौशल विकास तथा प्लेसमेंट तथा अभिनव परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा । शेष 80% आवंटन में से 10% केंद्र के पास रोक कर रखा जाएगा तथा बाद में बेहतर निष्पादन वाले राज्यों को मांग पर अतिरिक्त किश्त के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा । वित्त वर्ष की शुरूआत से पूर्व प्रत्येक राज्य को राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच गरीबी की पारस्परिक स्थिति के आधार पर एक निदर्शनात्मक आवंटन प्राप्त कराया जाएगा ताकि राज्य अपनी योजनाएं तैयार कर सकें । योजनाओं का एनआरएलएम / अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा तथा इन्हें अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुमोदित परिव्यय राज्य के लिए निदर्शनात्मक आवंटन से अधिक नहीं होगा । राज्यों की योजनाओं के मूल्यांकन में विभिन्न घटकों के बीच आवंटन को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें राज्यों में प्रारंभिक स्थिति को तथा वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए (सामाजिक जुटाव की मात्रा, वित्तीय अंतर्वेशन की सीमा इत्यादि) । ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति राज्य कार्य योजना को अनुमोदित करेगी ।

निधियों की रिलीज के लिए पद्धति

एनआरएलएम की औपचारिक शुरूआत से 12 महीने के भीतर सभी राज्यों द्वारा एनआरएलएम को अपनाया जाना है । अतः इस अवधि के दौरान कुछ राज्यों में एसजीएसवाई तथा एनआरएलएम दोनों समानांतर रूप से कार्यान्वित होंगे । तदनुसार वित्तपोषण के दो चरण होंगे । जिन राज्यों ने एनआरएलएम को अपनाने की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है उनके लिए निधियों की रिलीज तथा प्रवाह हेतु वित्तीय मानदण्ड तथा प्रक्रियाएं एसजीएसवाई की तरह ही रहेंगी । जो राज्य एनआरएलएम को अपनाने की परिस्थितियों का अनुपालन कर चुके हैं उनमें केंद्र से राज्यों को एनआरएलएम में

जाने वाली निधियां एसआरएलएम के माध्यम से जाएंगी । इसके लिए एसआरएलएम एक अलग बैंक खाता खोलेगा तथा इसे एनएमएमयू को अधिसूचित करेगा । एसआरएलएम वार्षिक कार्य योजना में दर्शाए गए जिले वार आवंटन के अनुसार जिले को निधियां रिलीज करेगा ।

एसआरएलएम को केंद्रीय अंश की रिलीज दो किश्तों में होगी : -

- **पहली किश्त** अप्रैल-मई के महीनों के दौरान राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के तथा समय-समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अध्ययधीन
- **दूसरी किश्त** अक्टूबर-दिसम्बर में एसआरएलएम के अनुरोध पर निर्धारित प्रोफार्मा में तथा निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर : -

➢ अथशेष सहित उपलब्ध निधियों के कम से कम 60% का उपयोग

➢ पिछले वर्ष के दौरान रिलीज राज्य सरकार का अंश (उसमें कमी के मामले में, केंद्रीय अंश को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा)

➢ एसआरएलएम का अथशेष पिछले वर्ष के आवंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए (यदि अथशेष इस सीमा से अधिक हो तो केंद्रीय अंश आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा)

➢ पिछले वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

➢ वार्षिक कार्य योजना के संदर्भ में उपलब्धि; तथा

➢ पिछली रिलीज के समय निर्धारित अन्य निबंधन एवं शर्तों को पूरा किया गया हो

केंद्र के पास रोक कर रखी गई राशि जो बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को आवंटित की जानी है वह उन्हें अतिरिक्त किश्त के रूप में निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर आवंटित की जाएगी ।

- 31 दिसम्बर तक कुल उपलब्ध निधियों के 75% से अधिक का व्यय
- वर्ष के लिए आवंटन से अधिक अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध; तथा
- मुख्य एनआरएलएम संकेतकों का निष्पादन

तथापि, अतिरिक्त राशि राज्य आबंटन की एक किश्त (50%) से अधिक नहीं होगी । यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाएगा कि गरीबी ग्रस्त राज्यों को उनका उचित आवंटन मिले तथा बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को गरीबी उपशमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिले ।

राज्यों को निर्धारित आवंटन में से किसी शेष निधि को उन सभी राज्यों को संवितरित किया जाएगा जिसने दूसरी किश्त उठाई है (उन राज्यों के अलावा जिन्हें पहले ही बेहतर निष्पादन के लिए अतिरिक्त निधियां मंजूर की जा चुकी है) । यह संवितरण चल रहे वित्त वर्ष के लिए राज्यों के आवंटन के अनुपात में किया जाएगा ।

जो राज्य एनआरएलएम आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं वहां निधियां एसजीएसवाई के अंतर्गत मौजूदा पद्धति के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाती रहेगी ।

व्यय की पात्र मदें

राज्य कार्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय की पात्र मदें निम्नानुसार हैं : –

(i) **संस्थान निर्माण -** प्रतिभागात्मक असुरक्षा आकलन, नए स्व सहायता समूहों का गठन / प्रोत्साहन, परिसंघ एवं अन्य समूह

(ii) **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण -** गरीबों की संस्थाएं, सीआरपी, स्टॉफ तथा अन्य भागीदार; इसमें ज्ञान संवितरण, शिक्षा तथा समर्थन शामिल है

(iii) **परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी**

(iv) **ब्याज सब्सिडी**

(v) **अवसंरचना सृजन तथा विपणन**

(vi) **कौशल तथा प्लेसमेंट परियोजनाएं**

(vii) **प्रशासनिक लागत -** अभियान (कार्यक्रम) प्रबंधन लागत जिसमें निगरानी, मूल्यांकन तथा शिक्षण शामिल है ।

फंड ट्रैकिंग सिस्टम

एनआरएलएम में एसआरएलएम स्तर पर एक व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है ताकि पारदर्शिता, दक्षता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके । एनआरएलएम एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित फंड ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करेगी तथा गरीबों की संस्थाओं में तथा समर्थन ढांचों में ई-बुक कीपिंग को बढ़ावा देगा ।

तथापि, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संगत सभी न्यासीय प्रबंधन प्रणाली / प्रक्रिया लागू होंगी ।

आर्थिक सहायता / वित्तीय मानक / उच्चतम सीमा

1. स्व सहायता समूहों का गठन - समूह गठन तथा विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों / सीबीओ / समुदाय समन्वयकर्ता / सुविधा प्रदाता / ऐनिमेटर को 10000 रू. प्रति स्व सहायता समूह दिए जाने हैं ।

2. परिक्रामी निधि - स्व सहायता समूह को कार्य के रूप में प्रति स्व सहायता समूह कम से कम 10000 रू. तथा अधिक से अधिक 15000 रू. । यह उन सभी स्व सहायता समूहों को दिया जाता है जिन्हें पहले परिक्रामी निधि प्राप्त न हुई हो । 70% से अधिक बीपीएल सदस्यों वाले स्व सहायता समूह परिक्रामी निधि के लिए पात्र हैं ।

3. पूंजीगत सब्सिडी - स्व सहायता समूहों तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की उच्चतम सीमा लागू है - सामान्य वर्ग के लिए 15000 रू. प्रति लाभार्थी तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा

विकलांग वर्ग के लिए 20000 रू. प्रति लाभार्थी । कोई स्व सहायता समूह अधिकतम 2.50 लाख रू. की सब्सिडी के लिए पात्र होता है । केवल बीपीएल सदस्य व्यक्तिगत सब्सिडी के पात्र हैं तथा केवल वे स्व सहायता समूह जिनमें 70% से अधिक सदस्य बीपीएल के हों, स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली सब्सिडी के पात्र हैं ।

4. क्षमता निर्माण तथा कौशल प्रशिक्षण - 7500 रू. प्रति लाभार्थी - इस घटक के अंतर्गत उपलब्ध राशि का न केवल लाभार्थियों के लिए अपितु कार्यक्रम अधिकारियों तथा स्टाफ, समुदाय व्यवसायियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज कर्मियों इत्यादि सहित अन्य सभी भागीदारों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है । प्रदर्शन दौरों पर तथा निमग्नता दौरों पर होने वाला व्यय भी इस घटक के अंतर्गत कवर किया जाता है । कौशल निर्माण प्रशिक्षण का तात्पर्य है स्व रोजगार के लिए सदस्य स्तर प्रशिक्षण तथा यह प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रशिक्षण तथा आरएसईटीआई प्रशिक्षण से अलग है ।

5. ब्याज सब्सिडी - बैंकों से लिए गए सभी स्व सहायता समूह ऋणों के लिए 7% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज पर सब्सिडी, तुरंत पुनर्भुगतान पर आधारित । ब्याज सब्सिडी स्व सहायता समूहों को उनके सदस्यों को अंतरण के लिए उपलब्ध कराई जाती है जब तक वे 1.00 लाख रू. की राशि तक का बैंक ऋण न ले चुके हों । यह अपेक्षित है कि स्व सहायता समूहों में सदस्यों को वित्तपोषण की किश्तें पुनः दी जाएगी तथा 1.0 लाख रू. की यह सीमा सदस्य द्वारा लिए गए कुल ऋण की है । यह सब्सिडी ऐसे अवसरों पर उपलब्ध नहीं है जब स्व सहायता समूह पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त कर रहा हो।

6. परिसंघों के स्थायित्व तथा प्रभाविकता के लिए कार्य निधि के लिए एक मुश्त अनुदान -

   - ग्राम / पंचायत स्तर परिसंघ के लिए 10000 रू.
   - ब्लॉक स्तर परिसंघ के लिए 20000 रू.
   - जिला स्तर परिसंघ के लिए 100000 रू.

7. प्रशासनिक व्यय - आवंटन का 5%, कौशल विकास तथा प्लेसमेंट से संबंधित घटक का निवल तथा आरएसईटीआई के घटक का निवल । यह राज्यों को केंद्रीय रिलीज तथा तदनुसार राज्य अंश का 5% है ।

8. अवसंरचना तथा विपणन - आवंटन के केंद्रीय अंश तथा तदनुसार राज्य अंश अर्थात राज्य के कार्यक्रम परिव्यय का 20% (पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में 25%) तक ।

9. कौशल तथा प्लेसमेंट परियोजनाएं तथा अभिनवता (केंद्रीय आवंटन का 20%) - अभिनव परियोजनाओं पर व्यय 5% से अधिक नहीं होना चाहिए; तथा शेष 15% प्लेसमेंट सह कौशल विकास परियोजनाओं के लिए है । प्लेसमेंट सह कौशल विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन (केंद्रीय आवंटन का 7.5%) का 50% बहु राज्य कौशल विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र में बहाल रखा जाता है तथा शेष को राज्य विशिष्ट कौशल विकास तथा प्लेसमेंट परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को आवंटित किया जाता है । इन राज्यों को उन्हें रिलीज की गई राशि में तदनुरूप राज्य अंश जोड़ना होता है ।

अध्याय - 9
कार्यान्वयन

एनआरएलएम मूल्यांकन की गई तथा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं तथा राज्य संदर्शी एवं कार्यान्वयन योजनाओं में से राज्यों का वित्तपोषण करेगी जिसमें परिणामों तथा इन परिणामों की प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई हो । इसमें से इन योजनाओं के निष्पादन की अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक तौर पर समीक्षा की जाएगी तथा राज्यों के लिए निधियों का अंतरण परिशोधित वार्षिक योजनाओं पर आधारित होगा ।

एनआरएलएम की ओर अंतरण

एक कार्यक्रम के रूप में एनआरएलएम, एसजीएसवाई की मजबूती पर आधारित है तथा इसमें देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित सफल ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों से सामने आने वाली बेहतरीन परंपराओं से प्राप्त सीख को भी शामिल किया गया है । एसजीएसवाई की तुलना में एनआरएलएम के अंतर्गत दो मुख्य कार्यनीतिक परिवर्तन निम्नानुसार हैं : -

i. एनआरएलएम मांग आधारित है तथा राज्य अपनी परिस्थिति तथा संदर्भ के आधार पर अपनी स्वयं की आजीविका आधारित गरीबी उपशमन कार्ययोजनाएं तैयार करते हैं ।

ii. एनआरएलएम राज्य स्तर से उप जिला स्तर तक कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक सहयोग ढांचे का प्रावधान करता है ।

इसे एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा तथा राज्य 5-7 वर्ष की अवधि में सभी जिलों को कवर कर लेंगे ।

सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र एनआरएलएम की औपचारिक शुरूआत से एक वर्ष के भीतर एनआरएलएम को अपना लेंगे । इसके बाद एसजीएसवाई के अंतर्गत वित्त पोषण को रोक दिया जाएगा ।

अंतरण में प्रारंभिक कदम

- एनआरएलएम में अंतरण के लिए नोडल अधिकारी को पदनामित करना । किसी राज्य में एसजीएसवाई के लिए जिम्मेदार आयुक्त / निदेशक सामान्यतया नोडल अधिकारी होगा; राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही एक समर्पित सोसायटी अस्तित्व में है । इनके राज्य सीईओ / एसपीडी (राज्य परियोजना निदेशक) को राज्य द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाएगा ।

- एनआरएलएम की ओर अंतरण के लिए प्रारंभिक कार्य में सहायता देने के लिए एक बहुविषयी कोर दल का गठन करना; इस दल के सदस्य सरकार, बैंकों, सिविल सोसाइटी संगठनों, शिक्षण तंत्र इत्यादि से लिए जाएंगे । इस दल में दक्षता के क्षेत्रों में शामिल होंगे - सामाजिक अंतर्वेशन, वित्तीय अंतर्वेशन, आजीविका, मानव संसाधन, कार्यक्रम प्रबंधन इत्यादि ।

- एक स्वायत्त निकाय के रूप में एसआरएलएम की स्थापना करना, तथा राज्य सरकार से राज्य मिशन निदेशक नियुक्त करना; एसएमएमयू तैनात करना तथा एसएमएमयू में स्टाफ तैनात करना ।
- यदि तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो एनआरएलएम / एनएमएमयू से प्रारंभिक कार्य में सुविधा देने के लिए तकनीकी सहायता; यह तकनीकी सहायता निम्नलिखित के लिए होगी :-
  - अन्य राज्यों में सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए प्रदर्शन दौरा
  - एसआरएलएम / एसएमएमयू की स्थापना
  - प्रारंभिक वार्षिक कार्य योजना का विकास (आईएएपी)
  - परिस्थिति विश्लेषण तथा भागीदारों के परामर्श; कार्यनीति कार्यशाला
  - मानव संसाधन नीति तथा भर्ती; मुख्य स्टाफ को शामिल करना तथा उनका क्षमता निर्माण
  - राज्य संदर्श तथा कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) तैयार करना
  - मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए एनआरएलएम / ग्रामीण विकास मंत्रालय को आईएएपी तथा / अथवा एसपीआईपी प्रस्तुत करना

एनआरएलएम को सफलतापूर्ण अंतरण करने के लिए अपेक्षित है कि वह एक स्वायत्त एसआरएलएम की स्थापना करे, पहले चरण के जिलों तथा ब्लॉकों में एनआरएलएम क्रियाकलाप शुरू करने के लिए राज्य, जिला तथा उप जिला स्तर पर अपेक्षित तथा शामिल / प्रशिक्षित स्टाफ तैनात करे, तथा पहले वर्ष के लिए एक प्रारंभिक कार्य योजना तथा / अथवा वार्षिक कार्य योजना के साथ एसपीआईपी प्रस्तुत करें । इसके एनआरएलएम / ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन तथा अनुमोदन पर राज्य एनआरएलएम / एनएमएमयू तथा एसआरएलएम के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से एनआरएलएम को औपचारिक तौर पर अंतरित करेंगे । तत्पश्चात प्रस्तुत किए जाने वाले एसपीआईपी स्वतः ही समझौता ज्ञापन का अंग समझे जाएंगे ।

एनआरएलएम कार्यान्वयन के लिए योजना बनाना

एसएमएमयू सभी जिला कार्य योजनाओं को समेकित करते हुए तथा एसएमएमयू कार्य योजना शामिल करते हुए एसपीआईपी तैयार करेगी । एसएमएमयू अपने शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित एसपीआईपी को एनआरएलएम / ग्रामीण विकास मंत्रालय को आकलन तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी । राज्य की तैयारी के आधार पर, इसमें एनआरएलएम की औपचारिक शुरूआत से 6-12 माह तक का समय लग सकता है । इस दौरान राज्य पहले वर्ष के लिए 31 दिसम्बर तक प्रारंभिक वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा ।

प्रारंभिक वार्षिक कार्य योजना (आईएएपी): पहले वर्ष के लिए आईएएपी एक वर्ष के लिए कार्य की एक सरल योजना है । इससे मौजूदा कार्यान्वयन समर्थन ढांचों को स्पष्टता दी जा सकेगी । वर्ष में राज्य के लिए संसाधन की उपलब्धता के मोटे तौर पर संकेत के आधार पर प्रत्येक एसआरएलएम प्राथमिकता वाले कार्य शुरू करेगा तथा आईएएपी तैयार करेगा (यदि उन्होंने एसपीआईपी प्रस्तुत न किया हो) । आईएएपी के मुख्य तत्वों में शामिल है -

- एसआरएलएम तथा एसएमएमयू की पृष्ठभूमि तथा ब्यौरा
- वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी युक्ति का इस्तेमाल करते हुए कार्यान्वयन के लिए चुने गए जिले तथा ब्लॉक तथा उनका ब्यौरा
- जुटाव तथा संपर्क के नियोजित तथा मुख्य परिणामों के चरण बनाना - परिवार, स्व सहायता समूह, संस्थान, ग्राम, समूह, ब्लॉक, जिले ।
- स्टाफिंग; स्टाफ शामिल करना तथा क्षमता निर्माण योजना
- संस्थाओं में सीआरपी कार्यनीति तथा क्षमता निर्माण, संस्थानों में मानव संसाधन, प्रापण ।
- आईटी, एमआईएस, संचार, तालमेल तथा भागीदारी के लिए योजनाएं
- तकनीकी सहायता / सहायता योजना
- अध्ययन / दृष्टिकोण पत्र, स्थिति विश्लेषण, परामर्श / कार्यशाला के लिए योजना
- 5-6 वर्षीय एसपीआईपी तैयार करने के लिए योजना
- कार्य समयावधि; कार्य-समय-लागत-जिम्मेदारी मैट्रिक्स
- बजट

आईएएपी का मूल्यांकन तथा अनुमोदन राज्य से किसी अन्य वार्षिक कार्य योजना की तरह किया जाएगा । रिलीज अनुमोदित आईएएपी के अनुसार की जाएगी ।

चरण बनाना

गरीबों द्वारा स्वयं संचालन के लिए एनआरएलएम को गरीबों की सामाजिक पूंजी को विकसित करने की जरूरत है । इसमें प्रारंभिक वर्षों में कुछ समय लगेगा किंतु आगे चल कर यह कई गुना हो जाएगी । व्यवसायी स्टाफ की उपलब्धता भी प्रारंभ में सीमित रहेगी । यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हस्तक्षेपों की गुणवत्ता तथा प्रभाविकता कम न हो पाए । इसलिए, राज्य से अपेक्षित है कि वे 5-7 वर्ष में एक चरणबद्ध तरीके से राज्य में सभी जिलों तथा ब्लॉकों को कवर करे । राज्य को प्रत्येक चरण में उन जिलों तथा ब्लॉकों की पहचान करने तथा एक स्पष्ट शुरूआती योजना तैयार करने की जरूरत होगी। राज्यों द्वारा प्रारंभिक गहन जिलों तथा ब्लॉकों के चयन के लिए व्यापक मानदण्डों में शामिल है -

(i) राज्य के विभिन्न सामाजिक - आर्थिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाला प्रत्येक चरण (ii) गरीब जिले / ब्लॉक पहले ; तथा (iii) स्व सहायता समूहों तथा सफलतापूर्वक आजीविका कार्यक्रम चला रहे जिले / ब्लॉक तथा उच्च सामाजिक पूंजी पहले ।

पुरा (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान) समूह गहन एप्रोच के अंतर्गत कवर की जाएगी ।

संपूर्ण राज्य आधार पर पहले से ही एनआरएलएम प्रक्रिया को कार्यान्वित कर रहे राज्य (आंध्र प्रदेश तथा केरल जैसे) सीधे ही संपूर्ण राज्य एनआरएलएम में चले जाएंगे । इनमें से प्रत्येक राज्य मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए पूरे राज्य को कवर करने वाली एसपीआईपी तथा वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेगा । तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, असम तथा मणिपुर जैसे राज्य पहले ही बहु पक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से वित्त पोषित वृहत ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं । इसी प्रकार राजस्थान तथा नागालैंण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा तथा सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य बहु पक्षी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं । इन सभी राज्यों की कार्य योजना में इन राज्यों में चल रहे ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम तथा एनआरएलएम तथा चल रहे कार्यक्रमों के बीच तालमेल की स्थिति दर्शानी चाहिए ।

यदि एनआरएलएम के लिए जिले तथा ब्लॉक नहीं चुने जाते तो गैर-गहन ब्लॉकों के लिए दिशानिर्देश लागू होंगे । राज्य अपने लिए समेकित योजना पर पहुँचने के लिए गहन तथा गैर-गहन ब्लॉकों के लिए अलग कार्य योजना बनाएंगे ।

जिन ब्लॉकों को एनआरएलएम कार्यान्यवयन के लिए लिया गया है, उन ' गहन ब्लॉकों' की प्रशिक्षित पेशेवर स्टाफ तक पहुँच होगी तथा इसमें व्यापक तथा गहन सामाजिक अंतर्वेशन, आजीविका, भागीदारी इत्यादि के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा।' गहन ब्लॉकों' के कार्यक्रमों का एक पूरा क्षेत्र होता है । इसमें शामिल है : -

i ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम में सभी पहचाने गए बीपीएल परिवारों का पूरी तरह से जुटाव[7]

ii गरीबों की संस्थाओं - स्व सहायता समूहों तथा प्राथमिकता परिसंघों को बढ़ावा

iii सामाजिक पूंजी अथवा समुदाय पेशेवरों के वृहत आधार का सृजन तथा सशक्तीकरण

iv स्व सहायता समूहों को परिक्रामी निधि

v निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक के समर्थन के लिए प्राथमिक परिसंघों को पूंजीगत सब्सिडी

- गरीबों के लिए सुरक्षा तंत्र तथा छोटे अनुदान
- अपने एमआईपी से स्व सहायता समूहों को आगे ऋण देना
- स्वास्थ्य बचत के पूरक के लिए स्वास्थ्य जोखिम निधि
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा
- निचले स्तर पर आयोजना, प्रौद्योगिकी संवितरण इत्यादि जैसी सेवाओं का निष्पादन

vi एमआईपी का वित्त पोषण करने के लिए स्व सहायता समूहों तथा प्राथमिक परिसंघों को बैंक वित्त पोषण

vii कृषि, पशुधन, गैर कृषि, कौशल जैसी चुनिंदा गरीब परक आजीविकाओं में क्रियाकलाप -

- विशेष आजीविका संस्थान तथा उत्पादन संग्रह :

[7]संतृप्त एप्रोच में ब्लॉक में सभी ग्रामों में सभी गरीब तथा कमजोर परिवारों की कवरेज अनिवार्य है ।

- उत्पादकता वृद्धि पहलकदमी तथा सामुदायिक विस्तार मॉडल
- छोटे पैमाने की उत्पादक अवसंरचना तथा स्थानीय मूल्य संवर्धन
- सामूहिक निवेश खरीद तथा सामूहिक विपणन
- निवेश तथा उपभोग मदों की लागत में न्यूनीकरण; इत्यादि

viii सभी को हकदारी, सार्वजनिक सेवाओं तथा आजीविका समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी

तथापि, शेष ब्लॉकों ' गैर-गहन ब्लॉक' में, पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा / अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में सीमित स्टॉफ के साथ ये क्रियाकलाप विस्तार तथा गहनता में सीमित होंगे -

i. मौजूदा स्व सहायता समूहों का सशक्तीकरण तथा बीपीएल महिलाओं के नए सजातीय-आधारित स्व सहायता समूह गठित करना
ii. स्व सहायता समूहों तथा स्व सहायता समूह नेताओं का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण
iii. स्व सहायता समूहों को परिक्रामी निधि उपलब्ध कराना
iv. बैंक वित्त पोषण वाले स्व सहायता समूहों को पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध करना
v. वाटरशेड, डेयरी इत्यादि जैसी मौजूदा स्थानीय स्तर की आजीविका पहलकदमियों सहित मुख्य धारा की संस्थाओं के साथ संपर्क ।

तथापि, आरएसईटीआई का स्व रोजगार / उद्यमिता विकास तथा कौशल विकास / प्लेसमेंट गहन तथा गैर-गहन ब्लॉकों, सभी जिलों में मौजूद होगा ।

परिस्थिति विश्लेषण - मौजूदा स्थिति का आकलन

एसपीआईपी तैयार करने में पहले और महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है परिस्थिति विश्लेषण - मौजूदा स्थिति का आकलन/गरीबों को गरीबी से निदान दिलाना, इसमें द्वितीयक आंकड़े, नमूना भागीदारी आकलन तथा त्वरित अध्ययन का इस्तेमाल किया जाता है । टेम्प्लेट 1, अनुबंध 4 में पारिस्थितिक विश्लेषण में तत्व देखें ।

इसकी परिणति भागीदारों के परामर्श में एनआरएलएम कोर मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा परिस्थिति विश्लेषण पर आधारित कार्यनीति के मसौदा समूह पर चर्चा करते हुए तथा उन्हें दुरुस्त करते हुए समुदाय नेताओं, सिविल सोसाइटी, बैंकरों तथा सरकारी विभागों के साथ विचारों के आदान-प्रदान की कार्यशाला के रूप में होगी।

राज्य संदर्शी तथा कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) तथा वार्षिक कार्य योजना

एसपीआईपी राज्य में व्यापक रूप से गरीबी कम करने के लिए एक दीर्घावधि योजना है तथा यह चरणबद्ध तरीके से

परिणामों, कोर कार्यनीतियों तथा मुख्य क्रियाकलापों की रूपरेखा देता है । यह एक परिवर्तनशील दस्तावेज है तथा यह कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति से प्राप्त सीख/ जानकारी के आधार पर नियमित तथा आवधिक परिशोधनों के अध्यधीन है । परिणामों, कार्यनीतियों तथा क्रियाकलापों के अलावा, यह चरणबद्ध तथा समयबद्ध तरीके से इस परिणामों की प्राप्ति के लिए कार्यान्वयन प्रबंधों तथा वित्तीय संसाधनों की जानकारी भी देती है ।

प्रत्येक एसआरएलएम एक प्राथमिकता देने तथा एसपीआईपी का मसौदा तैयार करने का क्रियाकलाप शुरू करेगा । एसपीआईपी में मुख्य तत्वों के लिए अनुबंध 4, टेम्पलेट 2 देखें ।

इस प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, संसाधनों के आवंटन के मानदण्डों से यथाशीघ्र एक दूसरे को अवगत कराया जाएगा। अंतिम राज्य-अनुमोदित एसपीआईपी एनआरएलएम / ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

एसपीआईपी तथा वार्षिक कार्य योजना का मूल्यांकन

एसपीआईपी की प्राप्ति पर एनआरएलएम / एनएमएमयू प्रारंभ में जांच सूची के अनुपालन तथा राज्य में गरीबी की स्थिति से निपटने की तैयारी तथा एनआरयूएम के लिए व्यापक प्राथमिकताओं तथा परिणामों के लिए एक डेस्क मूल्यांकन के माध्यम से इसकी जांच (विशेष रूप से गठित जांच दल) करेगा ।

एनआरएलएम, यदि संतुष्ट हो तो एक बहु विषयी संयुक्त मूल्यांकन मिशन तैनात करेगा[8] । मूल्यांकन मिशन फील्ड स्थानों के दौरों, प्रतिभागात्मक आकलन, मुख्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों तथा चर्चाओं तथा एसपीआईपी की समीक्षा करने तथा उसे बेहतर बनाने के लिए राज्य स्तर की बहु-भागीदार कार्यशालाओं सहित कई पद्धतियों का इस्तेमाल करेगा । यह विशेष रूप से एसआरएलएम की चरणबद्धता, कार्यनीति तथा परिणामों; स्टाफिंग, विभिन्न स्तरों पर इकाइयों की कार्यान्वयन क्षमता; सरकारी विभागों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, जन संस्थाओं इत्यादि; के साथ सहभागिता तथा प्रशासनिक और न्यासीय प्रबंधों का मूल्यांकन करेगा तथा अपनी सहमति जताएगा ।

आकलन मिशन के साथ सहमत क्रियाकलापों के आधार पर एसआरएलएम अपनी परिशोधित एसपीआईपी तथा वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा । टीएससी / आकलन मिशन परिशोधित एसपीआईपी की तथा वार्षिक योजनाओं की समीक्षा करेगा तथा एसपीआईपी के अनुमोदन के लिए एक आकलन दस्तावेज तैयार करेगा। बाद के वर्षों के लिए, टीएससी एसपीआईपी तथा पर्यवेक्षण मिशन द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक, समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन तथा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम परिमाणात्मक / गुणात्मक निष्पादन मानदण्डों के संदर्भ में वार्षिक कार्य योजनाओं का आकलन करेगा।

एसपीआईपी तथा वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन

ग्रामीण विकास मंत्रालय / एनआरएलएम अधिकार संपन्न समिति अनुमोदन के लिए आकलन के पश्चात आकलन दस्तावेज के साथ अंतिम रूप से परिशोधित योजना पर विचार करेगी । इस प्रक्रिया के दौरान एसएमडी तथा / अथवा राज्य सचिव, ग्रामीण विकास प्रस्तुति देंगे । आवंटन फार्मूला के अनुसार राज्यों को उपलब्ध आवंटन सहित सभी पहलुओं

[8]आकलन प्रक्रियाओं / पद्धति से संबंधित दिशानिर्देश नोट तथा अलग से उपलब्ध आकलन मिशन की भूमिका अलग से उपलब्ध है (तीन वर्षों में कम से कम 80%)

पर विचार करते हुए यह समिति उपयुक्त परिशोधन के साथ अपना अंतिम अनुमोदन देगी तथा इस अंतिम रूप से अनुमोदित एसपीआईपी, सहमत परिणामों तथा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार संसाधन आवंटित करेगी । तब एनआरएलएम / एनएमएमयू तथा एसआरएलएम / एसएमएमयू एसपीआईपी को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन करेंगे अथवा समझौता ज्ञापन में एक परिशिष्ट जोड़ेंगे । एनआरएलएम / एनएमएमयू जिस वित्त वर्ष में एसपीआईपी प्रस्तुत किया जाए उस वित्त वर्ष की 15 मार्च तक अनुमोदन क्रियाकलाप पूरे करना सुनिश्चित करेगा ।



तब, एनआरएलएम / एनएमएमयू एसआरएलएम की कार्यान्वयन तत्परता देखेगी - पूर्णतः शामिल किया गया दल; मानव संसाधन नीति तथा नियमावली; प्रशासनिक एवं वित्तीय नियम; निर्धारित भागीदार तथा भागीदारी के लिए फ्रेमवर्क; तथा प्रचालन नियमावली । एसआरएलएम की तत्परता से संतुष्टि पर एनआरएलएम / एनएमएमयू एसआरएलएम विशेष बैंक खाते में वर्ष में दो में से पहली किश्त जारी करेगा (अर्थात वार्षिक आवंटन का 50%) तथा औपचारिक रूप से एसपीआईपी की शुरूआत करेगी ।

बाद की वार्षिक योजनाएं तथा किश्त

जैसे-जैसे एसपीआईपी कार्यान्वयन आगे बढ़ेगा, बाद की किश्तें अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा, वार्षिक समीक्षा तथा योजनाओं तथा पहले रिलीज की गई किश्त / किश्तों के उपयोग तथा शेष उपलब्ध निधियों के अध्ययधीन होंगी । अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा मिशन इस योजना (वार्षिक योजना तथा एसपीआईपी) तथा समय-समय पर एनआरएलएम द्वारा निर्धारित न्यूनतम परिमाणात्मक / गुणात्मक निष्पादन मानदण्डों की तुलना में कार्यान्वयन समीक्षा करेगा ।

किसी वर्ष विशेष में राज्य के पास संसाधन की उपलब्धता के व्यापक संकेत के आधार पर एसआरएलएम एक प्राथमिकता देने वाली गतिविधि शुरू करेगा तथा एसपीआईपी से तालमेल करके वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा । राज्य अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना[9] तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रवाही योजना हर वर्ष 15 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व एनआरएलएम / एनएमएमयू पहुँच जानी चाहिए । वार्षिक कार्य योजना में तत्वों के लिए अनुबंध 4 टेम्पलेट 3 देखें ।

वार्षिक समीक्षा तथा आयोजना मिशन आगामी तीन वर्षों के लिए इन योजनाओं की समीक्षा करेगा । समीक्षा तथा आयोजना मिशन पिछले मिशनों तथा अन्य अध्ययनों, अब तक निष्पादन की स्वयं समीक्षा, तथा सहमत आवंटन मानदण्डों अथवा अन्य तरीके से तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध निधियों द्वारा दिशानिर्देशित होगा । तदनुसार, यह अपनी सिफारिशें करेगा । इस सिफारिश के आलोक में, इन योजनाओं (परिशोधित, यदि समीक्षा तथा आयोजना मिशन द्वारा सिफारिश की गई हो) पर विचार करेगी तथा अनुमोदन देगी । रिलीज निम्नानुसार दी जाएगी -

[9]वार्षिक कार्य योजना : मुख्य तत्व टेम्पलेट 3, अनुबंध 4 को देखें ।



एनआरएलएम / एनएमएमयू अनुमोदन क्रियाकलाप की पूर्ति हर वर्ष 15 मार्च तक सुनिश्चित करेगा ।

वार्षिक कार्य योजना : मुख्य तत्व टेम्पलेट 3, अनुबंध 4 को देखें ।

अनुबंध- I

केंद्र स्तरीय समन्वय समिति-संघटन

1.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य*
3.	डिप्टी गर्वनर	सदस्य
4.	सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य*
5.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य *
6.	सचिव, महिला और बाल विकास विभाग	सदस्य*
7.	सचिव, लघु एवं कृषि संबंधित उद्योग विभाग	सदस्य*
8.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता - मंत्रालय	सदस्य*
9.	सचिव, जनजातीय कल्याण मंत्रालय	सदस्य*
10.	अध्यक्ष, नाबार्ड	सदस्य
11.	सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग	सदस्य
12.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
13.	ग्रामीण विकास के राज्य सचिव	सदस्य
14.	सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
15.	महानिदेशक, कपार्ट	सदस्य
16.	महानिदेशक, एनआईआरडी	सदस्य
17.	अध्यक्ष, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन	सदस्य
18.	ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नामित, गैर-सरकारी संघठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
19.	ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नामित, गरीबों की संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
20.	मिशन निदेशक/संयुक्त सचिव (एनआरएलएम)	संसद-सदस्य

* यदि सदस्य बैठक में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो नामित व्यक्ति का स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय उचित प्रक्रिया के बाद प्रतिनिधियों को नामित करेगा। समिति की बैठकों में जब भी उनकी मौजूदगी की जरूरत महसूस होगी, अन्य अधिकारियों/ गैर-अधिकारियों को बुलाया जा सकता है।

अनुबंध- II

एनआरएलएम की एडवाइजरी, समन्वय एवं अधिकार संपन्न समितियां

एनआरएलएम एडवाइजरी समिति (एनआरएलएम-एडवाइजरी समिति)

(i)	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ii)	मंत्री	सदस्य
(iii)	सचिव	सदस्य
(iv)	राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	प्रशिक्षण/शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	निगमित क्षेत्र/उद्योग संघों के प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	आरबीआई, नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	एनआईआरडी, कपार्ट आदि के महानिदेशक	सदस्य
(ix)	विशेषज्ञ (आर डी)/एनजीओ (3)	सदस्य
(x)	स्वसहायता समूहों के सदस्यों/परिसंघों के प्रतिनिधि	सदस्य
(xi)	सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार	संयोजक
(xii)	मिशन निदेशक, एनआरएलएम	सह-संयोजक

एनआरएलएम समन्वय समिति

(i)	सचिव, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii)	सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग	सदस्य
(iii)	अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
(iv)	महानिदेशक- एनआईआरडी	सदस्य
(v)	राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव(3)	सदस्यों
(vi)	गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ/बैंकर	सदस्य
(vii)	मिशन निदेशक (एनआरएलएम)	सदस्य-संयोजक

एनआरएलएम अधिकार सम्पन्न समिति

(i)	सचिव, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय	अध्यक्ष

(ii)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
(iii)	राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव	आमंत्रित
(iv)	गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ/बैंकर	आमंत्रित
(v)	मिशन निदेशक	संसद-संयोजक

परियोजना जांच एवं स्वीकृत समितियाँ :

नवीन आजीविका परियोजनाएं एवं विभिन्न-राज्य कौशल एवं नियोजन परियोजनाएं

(क) परियोजना जाँच समिति

(i)	मिशन निदेशक, एनआरएलएम	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक/उपसलाहकार(आरडी), योजना आयोग	सदस्य
(iii)	निदेशक/उप सचिव (आईएफडी), ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
(iv)	विशिष्ट आमंत्रित आजीविका(नवीन/बैंकिंग विशेषज्ञ)	सदस्य
(v)	संबंधित निदेशक/उपसचिव/ संयुक्त निदेशक	संयोजक

(ख) परियोजना अनुमोदन समिति

(i)	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii)	सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग	सदस्य
(iii)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
(iv)	महानिदेशक - कपार्ट	सदस्य
(v)	विशिष्ट आमंत्रित (ग्रामीण विकास विशेषज्ञ/बैंकर)	सदस्य
(vi)	एनएसडीसी का प्रधान कार्यकारी	सदस्य
(vii)	मिशन निदेशक(एनआरएलएम)	संसद-संयोजक

अनुबंध- III

एसआरएलएम राज्य समाज:
शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का संकेतात्मक संघटन

शाषी निकाय

शाषी निकाय का संकेतात्मक संघटन इस प्रकार हो सकता है :-

• मुख्य मंत्री या मुख्य सचिव	अध्यक्ष
• कृषि, पंचायत राज, एएचडी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, उद्योग, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी, एसडब्ल्यू, संस्थागत वित्त के मंत्री/सचिव	सदस्य
• ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
• प्रशिक्षण संस्थान, निगमित क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाओं से प्रतिनिधि	सदस्य
• आरबीआई, नाबार्ड, संयोजक एसएलबीसी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य
• विशेषज्ञ (आरडी)/गैर-सरकारी संघटन (3)	सदस्य
• स्व-सहायता समूह के सदस्यों/परिसंघों के प्रतिनिधि	सदस्य
• मुख्य सचिव/सचिव (आरडी)	सदस्य
• राज्य मिशन निदेशक (एसआरएलएम)	सह-संयोजक

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति का संकेतात्मक संघटन इस प्रकार हो सकता है :-

• मुख्य सचिव/विकास आयुक्त	अध्यक्ष
• मुख्य सचिव (आरडी)	उपाध्यक्ष
• आयुक्त/निदेशक-कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पशुपालन,उद्योग, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जनजाति कल्याण इत्यादि	सदस्यों
• नाबार्ड/आरबीआई/एसएलबीसी संयोजक के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्यों
• उद्योग संघ	सदस्य
• एसएचजी परिसंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
• राज्य मिशन निदेशक (एसआरएलएम)	संयोजक

टेम्पलेट 1 : स्थिति संबंधी विश्लेषण में अवयव

<u>स्थिति संबंधी विश्लेषण अवयव में ये भी शामिल हो सकते हैं :-</u>

- गरीबों के सांख्यकीय ब्यौरे (जिला-वार, ब्लॉक-वार, समूह-वार) ग्रामीण परिवार, बीपीएल परिवार, सामाजिक वर्गीकरण, दुर्बल समूहों का अनुपात ।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा स्थिति (एस एवं पी)
- गरीबों द्वारा मानी गई गरीबी (पी)
- गरीबों की प्रति व्यक्ति आय (एस)
- सामाजिक जुटान/समूहों/संस्था संबंधी स्थिति, संगठित गरीब, छोड़ दिए गए गरीब (एस एवं पी)
- ऋण संबंधी स्थिति, प्रति व्यक्ति उपलब्ध चालू औपचारिक ऋण, बैंक की उपलब्धता (एस)
- दुर्बलता चित्रण/विश्लेषण, आदिम दुर्बल जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे संवेदनशील समूहों की स्थिति अल्प संख्यकों, अशक्त, अकेली महिला, एचआईवी/एड्स से प्रभावित, वृद्ध निराश्रित आदि, आपदा संभावित जैसे दुर्बल समूहों की स्थिति (एस एवं पी)
- हकदारी, कवरेज (एस)
- सरकार में मौजूदा कार्यक्रम, कवरेज, निष्पादन (एस एवं पी)
- गरीबों को संसाधन प्रदान करना जिसमें भूमि, पानी, सार्वजनिक सम्पत्ति, पशुधन शामिल हैं।
- चित्रण-गरीबों की आजीविकाएं (संख्या, रोजगार के दिन, मौसम की स्थिति आदि) (एस)
- गरीबी एवं कलेक्टिव्स, सहकारिताएं (एस-अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट)
- रोजगार घटक- मजदूरी, नौकरी, स्वरोजगार, बेरोजगार, अल्प-रोजगार, आवश्यक कौशल, कौशल के रूप (एस)
- संगठित एवं असंगठित उद्यम (एस)
- विस्थापितों का विवरण (एस)
- पर्यावरणीय स्थिति-तटीय, मैदानी भूमि, पहाड़ी क्षेत्र, टैंक केसकेड्स, खान, वन, चरागाह भूमि, जैव-विविधता, जंतु और पौधा, एनटीएफपी (एस)
- सिविल सोसाइटी को समुदायों के साथ जोड़ना और उनके द्वारा दृष्टांतों, प्रक्रियाओं का अनुकरण करना तथा क्षमता का उपयोग करना
- निगमित सामाजिक जिम्मेदारा (सीएसआर) की स्थिति एवं व्यावसायिक भागीदारी (पी)
- मौजूदा बेहतर प्रक्रियाएं जिनमें इनके दुहराव की संभावना है (एस एवं पी)

एस : परवर्ती डाटा, पी : प्राथमिक डाटा

टेम्पलेट 2 : राज्य परिप्रेक्ष्य एवं कार्यान्वयन योजना-मूल तत्व

- राज्य की सामान्य रूपरेखा
- स्थितिगत विश्लेषण का सार- गरीबी/सामाजिक/आजीविका रूपरेखा एवं गरीबों की मूल आजीविका का विवरण आदि, गरीबी को कम करने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयास (अब तक)-(ब्यौरे अनुबंध में हैं)
- गरीबी घटना एवं आजीविका में वृद्धि लाने में राज्य की योजना, अगर कुछ हो तो
- सिविल सोसाइटी एवं अन्य राज्यों सहित राज्य के प्रयासों से सीखे गए पाठ
- राज्य का मानचित्र जिसमें निर्धनता की स्थिति को दर्शाने वाले जिले तथा ब्लॉक हैं।
- परियोजना परिप्रेक्ष्य एवं कार्यान्वयन योजना का सार
- दृष्टि, मिशन, मूल्य, मुख्य सिद्धांत, अ-परक्राम्य
- कार्यनीति-सामाजिक समावेशन, संघटन, संस्थाएं, ऋण, वित्तीय समावेशन, आजीविकाएँ, बाजार लिंकेज, रोजगार आदि
- 7 सालों तक परिणाम -

  कवरेज, संघटन, संपर्क, गरीबी से बाहर परिवार, प्रति परिवार की बढ़ी औसत आय, हासिल की गई प्रतिभूति (प्रतिभूतियाँ), कम किए गए जोखिम, स्व प्रबंधित संस्थाएं और उनका निष्पादन

- गरीबी उपशमन और आजीविका संवर्धण के मॉडल
- कार्यान्वयन कार्यनीति एवं फेसिंग
  - जिले, ब्लाक, गहन एवं गैर-गहन के लिए समूह
  - जिले तर्क/फेसिंग का औचित्य सहित, ब्लॉक्स, ग्राम पंचायतों, गाँवों का फेसिंग
  - घटक/उपघटक (लक्ष्य, परिणाम, क्रिया-कलाप, उप-क्रिया-कलाप, प्रक्रियाएं, व्यय एवं संसाधन घटकों के संदर्भ में फेसिंग, अगर कुछ हो तो)-
    - ✓ सार्वजनिक संस्थाएं, क्षमताएं - मौजूदा स्वसहायता समूहों एवं स्वसहायता समूह परिसंघों के कार्यों को देखने के लिए नीति, संस्थाओं एवं सहायता का नैदानिक मूल्यांकन।
    - ✓ निधियां- वित्तीय सहायता, समावेश (एक मुश्त अनुदान, सामुदायिक संस्थाओं का पूंजीकरण, आवर्ती आर्थिक सहायता, आबंटन सूत्र आदि), सुरक्षा तंत्र, स्वास्थ्य, पोषण एवं जोखिम निधियां, खाद्य सुरक्षा निधियां, सामाजिक विकास निधियां
    - ✓ विशिष्ट आजीविका संस्थाएं/सहायता (सामुदायिक आजीविकाएं विश्लेषण एवं आयोजना, आजीविका संघटनों का गठन, आधारभूत संरचना, पूंजीकरण, कौशल विकास, बिजिनेस इंक्युबेशन, कामकाजी पूंजी, संपर्क, बाजार ज्ञान एवं विकास, निधियों की सहायता)

- ✓ मानव संसाधन ; अभिनव कार्य (मोडलों का सृजन) एवं संपोषण निधि, परियोजना प्रबंधन, संकल्पना की गई तकनीकी सहायता।
  - चरण बद्धता (थैमेटिक), तर्क/चरण बद्धता का औचित्य सहित
  - संकेतक के साथ वर्ष-वार एवं घटक-वार परिणाम
  - इकाइयों के साथ क्रिया-कलाप समय-सीमा

- कुछ महत्वपूर्ण प्रगति/चक्र
  - परिवार, स्व-सहायता समूह, संस्था, गाँव, समूह, ब्लॉक, जिले, राज्य
- मिशन संरचना, लोगों की संस्थागत संरचनाएँ
- मानव संसाधन (पहचान, शामिल करना, क्षमता निर्माण)
  - सामुदायिक संस्थाओं में (नेता, कर्मचारी, सामुदायिक पेशेवर, वालंटियर, सीआरपी)
  - मिशन संरचनाओं में (स्तर, विशेषज्ञता, दल) एवं
  - बाहरी (तालमेल एवं भागदारी, संसाधित व्यक्तियों, संसाधित समूहों के पूल)
  - मानव संसाधन नीति, योजना एवं नियमावली
  - सामुदायिक एवं मिशन सहायता संरचनाओं के लिए क्षमता निर्माण योजना

- संचार योजना (आई ई सी)-समुदायों सहित विभिन्न भागीदारों के साथ
- प्रबंधन सूचना प्रणाली- डाटा बेस, लेन-देन आधारित एमआईएस, ई बुक कीपिंग, निगरानी एवं जानकारी-आधार रेखा-मध्य-अवधि एंड लाईन, प्रक्रिया निगरानी, भागीदारी निगरानी एवं जानकारी तंत्र आदि।
- पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक लेखा-परीक्षा

- प्रापण व्यवस्था एवं योजना, सामुददायिक प्रापण सहित
- ताल-मेल-भागीदारों, कार्यक्रमों, योजनाओं, संपर्कों, साझीदारों (गैर सरकारी संघठनों, बैंको, गरीबों की संस्थाएं, पीआरआई, संसाधन संघठनों)
- चालू कार्यक्रमों के साथ भागीदारी, मौजूदा व्यक्तियों की संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, एवं व्यावसायिक संघठनों

- सामाजिक मूल्यांकन एवं सुरक्षा उपाय एवं अतिसक्रिय कार्य योजना-दुर्बल विशिष्ट योजनाएं-लिंग, अपंग, दलित, जनजातीय एवं अल्पसंख्यक स्थिति-आधारित योजनाएं, उनके विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट कार्यान्वयन व्यवस्था
- पर्यावरण (संस्कृति, जैव-विविधता आदि सहित) सुरक्षा उपाय नीति एवं अति सक्रिय कार्य

- तकनीकी सहायता योजना (एनआरएलएम)

- नीचे से ऊपर तक- आयोजना, पुनरीक्षा और पुनः आयोजना प्रक्रिया

- वित्तीय प्रबंधन-सामुदायिक संस्थाओं एवं मिशन संरचनाओं में
    - अनुमोदन प्रक्रिया, शक्तियों का प्रत्यायोजन
    - निधियों की उपलब्धता, संस्थाओं को रिलीज के लिए उत्प्रेरक
    - लेखाकरण, खाता बही, कंप्यूटरीकरण/ई-बुक कीपिंग
    - आंतरिक लेखा-परीक्षा, सांविधिक लेखा-परीक्षा, सामाजिक लेखा-परीक्षा
    - वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वार्षिक लेखा
    - क्रियाकलाप आधारित एवं परिणाम आधारित लागत
- **बजट (वर्ष-वार, घटक-वार, स्रोत-वार), निधियों के स्रोत**

- पहला वर्ष (अथवा अठारह महीने)-महीने-वार, घटक-वार
    - त्रैमासिक आउटपुट
    - वर्ष के दौरान पूरे क्रियान्वित करने के लिए समय-सीमा के साथ विस्तृत क्रिया कलाप।
    - क्रिया कलाप-समय-लागत-जिम्मेवारी मैट्रिक्स
    - क्रिया-कलापों का पीईआरटी चार्ट/एम एस-परियोजना क्रिया-कलाप चार्ट
    - प्रापण योजना, मानव संसाधन योजना, क्षमता निर्माण योजना, तकनीकी सहायता योजना
- दूसरा वर्ष-त्रैमासिक
- उसके बाद-वर्ष-वार

- शब्दों, संक्षिप्त आदि की शब्दावली

टेम्पलेट 3 : वार्षिक कार्य योजना - मूल तत्व

- पृष्ठभूमि
- परियोजना परिप्रेक्ष्य एवं कार्यान्वयन योजना का सार (5-6 वर्षों तक परिणाम ढांचासहित)

- भावी योजना एंव पिछले वर्ष की योजना के तुलना में समग्र एवं घटक- वार प्रगति
- कुछ महत्वपूर्ण प्रगति/चक्र का निष्पादन
  - परिवार, स्वसहायता समूह, संस्थाएं, गाव, समूह, ब्लॉक, जिले, राज्य
- पिछली समीक्षा की एड-मेमरैस का अनुपालन

- 3- वर्षीय रोलिंग प्लॉन/वार्षिक प्लान
  - गरीबों की पहचान
  - संघटन
  - संस्थाएं-स्व-सहायता समूह, पहला/दूसरा/तीसरा/चौथा स्तर परिसंघ
  - दुर्बल वर्ग विशिष्ट योजनाएं-लिंग, अपंग, दलित, जनजातीय एवं अल्पसंख्यक स्थिति-आधारित योजनाएं
  - मानव संसाधन, संस्थाओं में स्टॉफ
  - संस्थाओं में क्षमता निर्माण
  - संस्थाओं में मानव संसाधन का क्षमता निर्माण
  - दूसरी दौर की पीढ़ी के समूह
  - वित्तीय समावेशन एवं बैंक संपर्क
  - आजीविका समावेशन एवं बाजार संपर्क
  - मिशन मानव संसाधन योजना, मिशन मानव संसाधन क्षमता निर्माण
  - संचार योजना
  - प्रापण योजना
  - पर्यावरण अति-सक्रिय योजनाएं
  - तालमेल तथा भागीदारी योजना
  - तकनीकी सहायता/सहायता योजना
  - अध्ययन/दृष्टिकोण दस्तावेज
  - प्रौद्योगिकी योजना
  - इकाइयों के साथ क्रिया कलाप टाइम-लाइन, क्रिया कलाप-समय-लागत जिम्मेवारी मैट्रिक्स
  - बजट (वर्ष-वार, घटक-वार, स्रोत-वार), निधियों के स्रोत

शब्दावली, संक्षिप्त नाम एवं उपयोग की गई संक्षिप्ति

सलाहकार समिति (एसी) :- राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण समिति में सीएसओ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, वित्तीय संस्थाएं, उद्योग परिसंघ, अकादमीशयन, गरीबी एवं विकास विशेषज्ञ एवं अन्य हैं।

एएचडीः पशु पालन विभाग

एपीएमएआरकेएफईडीः- आंध्र प्रदेश राज्य सहकारिता बाजार परिसंघ लिमिटेड

बैंक मित्र- ग्राहक संबंध प्रबंधक, जोकि स्वसहायता समूह का या समुदाय सदस्य है जिन्हें स्थानीय बैंकों में तैनात किया जाता है जिन्हें स्थानीय बैंकों में तैनात किया जाता है जो सामुदायिक सुविधा प्रदाता का कार्य करते हैं,

बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग) :ग्रामीण आबादी जो भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे है।

ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)- एक ब्लॉक स्तरीय इकाई जो ब्लॉक में एनआरएलएम के कार्यान्वयन को जांच करने के लिए है।

ब्रिज वित्तपोषणः- स्व सहायता समूहों के लिए मुख्य वित्तपोषण लाने के लिए प्राथमिक परिसंघों द्वारा मध्यवर्ती वित्तपोषण।

कपार्टः- लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद

सीबीओः- सामुदायिक आधारित संघटन

समन्वय समिति (सीसी) :- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्षता में मिशन क्रिया-कलाप की जाँच के लिए बनाई गई समिति

सीईओ जेडपीः- जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) :- राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एसआरएलएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) :- निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की पहुँच को बेहतर करने के लिए गरीब परिवारों की मांग पूरा करने के लिए निधि।

सामुदायिक सुविधाप्रदाताः- स्व सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों की गठन एवं उनकी सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सामुदायिक संसाधन व्यक्तिः- इसका अर्थ होगा बेहतर व्यवसायी एवं स्व सहायता समूहों एवं उनके सेवा प्रदाता के सदस्यों के बीच रोल मॉडल ।

सीएसः- पूंजी राज सहायता

सीएसओः- सिविल सामाजिक संघठन

सीएसपी : समुदाय सेवा प्रदाता

सीएसआरः- निगमित सामाजिक जिम्मेवारी

डीसीबीओः- जिला क्षमता निर्माण संघठन

मांग जनित कार्यनीतिः- राज्यों को गरीबी उपशमन के लिए अपनी कार्य नीति बनाना चाहिए।

डीएलआरसीः- जिला स्तरीय समीक्षा समिति

डीपीएमयूः- इसका अर्थ होगा जिला परियोजना प्रबंध इकाई जो जिले में दिशा-निर्देशों के अनुसार मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसीः- सोसायटी पंजीयक अधिनियम या जिला परिषद में जिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी जिसकी अलग पहचान है जो विभिन्न गैर-गरीबी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जाँच के लिए है।

ईओआईः- रुचि की अभिव्यक्ति

स्व सहायता समूहों का परिसंघः- 5 से 20 स्व सहायता समूहों का समूह। प्राथमिक परिसंघ सामान्यतः ग्रामीण स्तर पर होते हैं ब्लॉक में दूसरे स्तर का परिसंघ या गाँवों स्तर के समूह एवं जिला स्तर पर जिला स्तर के परिसंघ होते हैं जिनका अपने स्तर पर अपना उद्देश्य, कार्य और पहचान है।

जीओआईः- भारत सरकार

जीपीः- इसका अर्थ होगा ग्राम पंचायत।

ग्राम सभाः- जैसा पंचायत अधिनियम में परिभाषित है।

एचआईवीः- ह्यूमन इम्यूनो डेफिसियन्सी वाइरस

मानव संसाधन नीतिः- मिशन लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पेशावर संस्थागत संरचनाओं को बहल करने के लिए मानव संसाधन नीति।

एचआरडीः- मानव संसाधन विकास

आईसीटीः- सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी

आईएफडीः- समेकित वित्त विभाग

आईटीडीएः- समेकित जनजातीय विकास एजेंसी

केएसएवीः- ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति एवं नैतिक मूल्य

केवीआईसीः-खाद्यी एवं ग्राम उद्योग आयोग

केवाईसीः- अपने ग्राहक को जानो

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः- दिनांक सितम्बर 7, 2005 को अधिसूचित अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि लाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार है उन्हें 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना

एम/ओ एसडब्ल्यू मंत्रालयः- समाज कल्याण मंत्रालय

मैक्रो इंवेस्टमेंट प्लान :- साधारण निवेशों की सूची जिसे सदस्य स्वसहायता समूहों की वित्तीय सहायता से सदस्य करना चाहते हैं।

एमआईएसः- प्रबंधक सूचना प्रणाली

मिशनः- केंद्र स्तर पर एनआरएलएम एवं राज्य स्तर पर एसआरएलएम

एमओआरडीः- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

एमएसएमईः- सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्रालय

नाबार्डः- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

एनजीओः- गैर-सरकारी संघठन

एनआईआरडीः- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान

राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू)- राष्ट्रीय स्तर पर इकाई जिसमें विशेषज्ञों का बहु-विषयक दल मौजूद हों

एनएसडीसीः- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

एनटीएफसीः- गैर-इमारती वन उत्पाद

अधिकारी एवं कर्मचारीः- समाज के पूर्ण-कालिक या अंशकालिक कर्मचारी या विधिवत शक्ति प्राप्त किसी भी प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा विधिवत नियुक्त परियोजना और परामर्शदाता, फेलो एवं अनुसंधान स्टॉफ भी शामिल है, अगर कोई हो तो

समाज के अधिकारीः- समाज के सभी पद-धारक

परियोजना अनुमोदन समितिः- विशिष्ट परियोजनाओं को सहायता देने के बारे में निबंधन और शर्तों पर विचार करने के लिए समिति।

पीडी (डीआरडीए)- जिला ग्रामीण विकास का परियोजना निदेशक

पीडीएसः- लोक वितरण व्यवस्था

कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक - इसका तात्पर्य ऐसा नेटवर्क मॉडल है जो क्रियाकलाप की पूर्ति में औचकता की अनुमति देती है जिसमें ये उपाय शामिल हैं- (i) विशिष्ट क्रिया कलापों एवं उपलब्धियों की पहचान, (ii) क्रिया-कलापों का उचित क्रम निर्धारित करना, (iii) नेटवर्क डायाग्राम तैयार करना, (iv) प्रत्येक क्रिया-कलाप का समय निर्धारित करना, (v) महत्वपूर्ण तरीके निर्धारित करना, तथा (vi) परियोजना की प्रगति के अनुसार पीईआरटी चार्ट को अद्यतन करना

पीएफ- भविष्य निधि

पीएफटीः- उप समूह स्तर पर परियोजना सुविधा का दल।

पीएचसीः- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

गरीबों की भागीदारी की पहचान - इसका तात्पर्य है गरीबों की पहचान के लिए ऐसा तरीका जो परियोजना गांव में अत्यंत गरीब, विकलांग, दुर्बल, जन जातीय, गंभीर रूप से बीमार रोगी, घुमंतू एवं अन्य सीमांत समुदायों को पहचानने में सहायक करता है।

पीओः- परियोजना अधिकारी

पीपीसीपीः- सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी

पीपीपीः- सार्वजनिक निजी भागीदारी

पीपीपीपीः- सार्वजनिक-निजी-लोगों की भागीदारी

पीपीः- पंचसूत्र सिद्धांत जिसमें पांच समूह प्रबंधक आचरण जो इस प्रकार हैं -नियमित बैठकों, नियमित बचत, नियमित आपसी लेन-देन, ऋणों का समय पर पुर्नभुगतान एवं बही खाते को अद्यतन करना।

पीआरआईः- पंचायती राज संस्थाएं

परियोजना जाँच समितिः- विशिष्ट परियोजनाओं की जाँच के लिए केंद्र स्तर पर समिति

पीवीटीजीः- विशेष रूप से उपेक्षित जन जातीय समूह

आरबीआईः- भारत रिजर्व बैंक

आरएफः- परिक्रामी निधि

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं- जिसे ग्रामीण बीपीएल युवकों के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रत्येक जिले में बैंकों के जरिए स्थापित किया जाएगा।

स्व सहायता समूहः- 5-20 प्राथमिक ग्रामीण बीपीएल महिलाओं का समूह जो अपने सामाजिक एवं महिलाओं का समूह जो अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सामूहिक कार्य करने के लिए एक जुट हुई हैं।

एसएमडीः- राज्य मिशन निदेशक

एसएमएमयू/एसआरएलएमः- राज्य मिशन प्रबंधक इकाई/राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

राज्य परियोजना प्रबंधक इकाईः- परियोजना प्रशासन के लिए जिम्मेवार राज्य परियोजना इकाई।

तकनीकी सलाहकार समूहः- राष्ट्रीय स्तर पर निकाय, जो राज्यों के मूल्यांकन मिशनों को समन्वय करता है।

टीएफआईः- कुल वित्तीय समावेशन

परियोजनाः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

यूटीः- संघ राज्य क्षेत्र

वीडीसी/वीओः- ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण विकास समिति/ग्रामीण संघठन

वीपीआरसीः- ग्रामीण गरीबी उपशमन समिति

डब्ल्यूसीडीः- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

जिला पंचायत उप समितिः- सरकार द्वारा अधिसूचित जिला पंचायत उपसमिति